राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 332 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार , 10 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

रैपर आदित्य तिवारी जबलपुर में मिला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पिछले दिनों ट्रोलिंग से परेशान होकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यमुना में कूदने की बात लिखकर लापता हो जाने वाले दिल्ली के रैपर आदित्य तिवारी को पुलिस ने खोज निकाला है। दिल्ली पुलिस ने उसे मध्यप्रदेश के जबलपुर से खोज निकाला। आदित्य 1 जून को इंस्टाग्राम पर यमुना में कूदने की बात लिखकर गायब हो गया था। 4 जून को महरौली थाने में उसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था। आदित्य की मां दीपा ने बताया था कि सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जा रहा था और उसे जान से मारने की धमकियां मिल रहीं थी। इसी वजह से उनका बेटा गायब हो गया है।

चीनी कंपनियों ने 150 करोड़ का लगाया चूना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चीनी नागरिकों के एक समूह द्वारा चलाए जा रहे एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये लोग धोखे से डेटा चुराकर उसे पॉवरबैंक, सनफैक्टरी और ईज़प्लान जैसे नकली निवेश ऐप के माध्यम से 150 करोड़ रुपए ठगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी (साइबर सेल) अन्येश रॉय के मुताबिक इन लोगों ने पांच लाख भारतीयों को ठगा है। एप गूगल पे स्टोर पर सूचीबद्ध है और निवेश पर आकर्षक और त्वरित रिटर्न प्रदान करता है। ये लोग एप के माध्यम से पैसा दुगुना करने का लालच दिया करते थे। पुलिस ने ऐसे 11 धोखेबाज चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

पंजाब के दो गैंगस्टर कोलकाता में ढेर

कोलकाता, (एजेंसी)। पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बुधवार को दो गैंगस्टर्स को गोलियों से उड़ा दिया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन दोनों गैंगस्टर्स की पुलिसवालों की हत्या से संबंधित केस में तलाश थी। अधिकारी ने बताया कि पंजाब में दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की हत्या को लेकर गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर और जसप्रीत सिंह की तलाश थी। उसे कोलकाता में एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया। एक सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस को कोलकाता पुलिस की मदद से भुल्लर और जसप्रीत सिंह को मारने में कामयाबी मिल पाई।

आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 2021 का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को लगने जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा गुरुवार को सूर्य ग्रहण दोपहर 1.42 बजे शुरू होगा और भारत में शाम 6.41 बजे तक चलेगा। सूर्य ग्रहण 'रिंग ऑफ फायर' के रूप में होने जा रहा है। नासा के अनुसार, कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के कई हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत में सभी जगहों पर नजर नहीं आएगा। इस नजारे को आखिरी समय में बेहद कम समय के लिए लद्दाख की उत्तर सीमाओं और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शाम को 5 बजकर 52 मिनट पर देखा जा सकेगा।

महिला ने एक साथ 10 बच्चों को दिया जन्म

घाना, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने एक बार में 10 बच्चों को जन्म दिया है, जिसने पिछले महीने मोरक्को में नौ बच्चों को जन्म देने वाले मालियन हलीमा सिसे द्वारा बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। न्यूयॉर्कपोस्ट के अनुसार, गोसियाम थमारा सिथोल ने(37) शुरू में सोचा था कि उनके आठ बच्चे होने जा रहे हैं। लेकिन जब उसने सोमवार की रात को जन्म दिया, तो सिथोल और उनका परिवार 10 बच्चों को पैदा होते देखकर हैरान रह गया - पिछले स्कैन की तुलना में दो बच्चे ज्यादा थे। उसके पति, तेबोहो त्सोतेत्सी ने डिक्यूप्लेट्स के जन्म के बाद प्रिटोरिया न्यूज को बताया कि मैं खुश हूं।

मरीजों की तेजी से रिकवरी और ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करने में मददगार

कोरोना मरीजों की दवा 2-डीजी के लिए दो कंपनियां में हुआ करार

हैदराबाद ■ एजेंसी

कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जानी वाली दवा 2-डी ऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) को लेकर हैदराबाद स्थित सीएसआईआर- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) और फार्मास्युटिकल कंपनी ली फार्मा साथ आई हैं। 2-डीजी दवा के सिंथेसिस के लिए दोनों कंपनियों ने एक नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग समझौता किया है।

हाल ही में, डीआरडीओ और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा विकसित 2-डीजी को कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग के लिए इजाजत मिली है। 2-डीजी दवा मरीजों के तेज रिकवर होने और उनकी ऑक्सीजन निर्भरता को कम करने में काफी मददगार पाई गई। डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज ने इस दवा को पाउच के रूप में लॉन्च किया है, इसे पानी में घोलकर पीया जा सकता है। ये वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस व एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है।

डॉ श्रीवरी चंद्रशेखर (निदेशक सीएसआईआर-आईआईसीटी) ने कहा कि 2-डीजी के विकास में सीएसआईआर की भूमिका है। सीएसआईआर कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दवाओं के विकास में लगा हुआ है। ली फार्मा लिमिटेड के साथ समझौता कोविड के इलाज के लिए किफायती चिकित्सीय विकल्पों को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। ली फार्मा डीसीजीआई से मंजूरी लेने के लिए आवेदन करेगी। कंपनी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित अपनी फॉर्मूलेशन सुविधा से 2-डीजी पाउच का निर्माण और सप्लाई करेगी।

मरीज कोरोना से जीतने में कम समय ले रहे

2-डीजी दवा के बारे में बताया गया कि ये कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। यानी इसे लेने के बाद मरीज कोरोना वायरस से जीतने में कम समय ले रहे हैं, वह जल्दी ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें ऑक्सीजन की भी कम ही जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन वाली बात इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीते दिनों देश ने देखा है कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारणों सैंकड़ों मरीजों ने दम तोड़ा है।

नए केस घटे , पर 24 घंटे में 6 हजार से ज्यादा मौतें

नईदिल्ली, (एजेंसी)। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 93,828 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,91,82,072 हो गई। देश में लगातार दूसरे दिन एक लाख से कम नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 11,65,487 हो गई है। देश में संक्रमण से 6,138 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,59,695 हो गई है। देश में अभी 11,65,487 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, पिछले 24 घंटे में 1,48,951 मरीज स्वस्थ हुए जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों को आंकड़ा 2,76,45,225 हो गया।

राज्यों के पास वैक्सीन की 1.33 करोड़ खुराक : केंद्र

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीकों की 1.33 करोड़ से अधिक खुराक अब भी मौजूद हैं तथा तीन लाख से अधिक खुराकें अगले तीन दिन के भीतर उन्हें मिल जाएंगी। उसने बताया कि अब तक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं। ये खुराकें उन्हें भारत सरकार की ओर से निःशुल्क तरीके से तथा राज्यों द्वारा सीधे खरीद की श्रेणी में दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि कुल 23,74,21,808 खुराकों (बरबाद हुए टीकों समेत) का इस्तेमाल हुआ है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीकों की कुल 1,33,68,727 खुराक अब भी मौजूद हैं। अगले तीन दिन में और 3,81,750 खुराकें उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

कोवैक्सीन विवाद: असल असर जांचने को करेगी चौथे फेज का ट्रायल

एक स्टडी में कोवैक्सीन को कोविशील्ड के मुकाबले कम असरदार बताया

भारत में इस्तेमाल की जा रहीं कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के असर पर हाल में आई एक स्टडी पर आपत्ति जताने के बाद भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के फोर्थ फेज ट्रायल का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की रियल-वर्ल्ड इफेक्टिवनेस यानी वैक्सीनेट हो चुके लोगों में टीके के असल असर की जांच करेगी। दरअसल, हाल ही में आई एक स्टडी में कोवैक्सीन को कोविशील्ड के मुकाबले कम असरदार बताया गया है। भारत बायोटेक ने इस स्टडी को अवैज्ञानिक और पूर्वाग्रह पर आधारित बताकर खारिज किया है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वह जुलाई में कोवैक्सीन के थर्ड फेज के क्लीनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करेगी। दरअसल, कोलकाता-बेस्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इम्यून रेस्पॉन्स की तुलना करते हुए स्टडी की थी। स्टडी के मुताबिक, कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी बना रही है।

मुंबई में बारिश से जनजीवन प्रभावित

लोकल ट्रेनों, बसों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन हो चुका है और मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते करीब 30 लोकेशंस पर बसों के रूट को डायवर्ट करना पड़ा है।

मुंबई के मुंब्रा, कोपर खैराने, मोहाने, पनवेल, मलवानी वर्सोवा समेत कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा बताया देश की वित्तीय राजधानी में जलभराव, लोकल ट्रेन सेवाओं में रुकावट की खबर आ रही है और महाराष्ट्र सहित मुंबई में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों में मॉनसून के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। उप महानिदेशक (डीडीजी), आईएमडी मुंबई डॉ जयंत सरकार ने कहा मुंबई में मानसून आ गया है। सामान्य आगमन की तारीख हर साल 10 जून है, इस बार मानसून औसत आगमन की तारीख से पहले आ गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों में मध्यम बारिश/गरज के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई के कोलाबा और सांताक्रूज में मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 5.30 बजे के बीच क्रमशः 65.4 मिमी और 50.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण मुंबई में ब्रीच कैंडी का पूरा हिस्सा जलमग्न हो गया है और फुटपाथ भी जलमग्न हो गया है।

मप्र और बिहार के कई हिस्सों में प्री-मानसून बारिश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मप्र और बिहार के कई हिस्सों में प्री-मानसून बारिश जारी है। मप्र की राजधानी भोपाल, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, देवास, सागर और जबलपुर में बारिश हो रही है। इंदौर में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोपाल में बुधवार शाम बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह तक यहां भी मानसून पहुंच जाएगा।

सरकार का देश के किसानों को तोहफा, खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही, बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

(शेष- पेज 8 पर)

कैबिनेट का फैसला

- धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
- 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी

किसान अपनी आपत्ति तर्क के साथ रखें : तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी आपत्ति तर्क के साथ रखें, सरकार उसका समाधान करेगी। श्री तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आंदोलनकारी किसान संगठन सरकार के साथ जब चर्चा करना चाहेंगे, तब बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संगठन के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, उनकी आपत्ति क्या है, उसका जबाव न तो संसद में दिया गया और न ही किसान संगठनों ने दिया। कानूनों की खामियों का सरकार निराकरण करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की ओर से चर्चा के दौरान ठोस प्रस्ताव दिया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्र ,चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और नव निर्वाचित चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ नई दिल्ली में।

गौतम थापर पर कसा सीबीआई का शिकंजा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सीबीआई ने वर्ष 2017-19 के बीच 466 करोड़ से अधिक सरकारी धन कथित रूप से यस बैंक में लगाने के मामले में दिल्ली तथा एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी की। इससे पूर्व, इस मामले में गौतम थापर, अवंथा रियल्टी तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सरकारी धन को कथित तौर पर यस बैंक में लगाने से जुड़े एक अन्य मामले में थापर के खिलाफ पहले ही जांच की जा रही है। वर्तमान मामले में सीबीआई ने रघुबीर शर्मा, राजेंद्र मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंथा रियल्टी प्रा.लि. के खिलाफ तथा झाबुआ पॉवर लि. के अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जितिन की एंट्री से यूपी के तराई क्षेत्र में भाजपा को मिलेगी मजबूती

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण विरोधी साबित करने की मुहिम को हवा दे रही कांग्रेस को जितिन प्रसाद की बगावत से तगड़ा झटका लगा है। वहीं, भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों को गति देने से पूर्व अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि सत्ता में वापसी के लिए हर दांव चलेंगे और अन्य दलों के दमदार नेताओं से भी गुरेज न किया जाएगा।

खासकर उन क्षेत्रों में, जहां भाजपा को अपनी स्थिति और मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की भाजपा में एंट्री को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर व पीलीभीत से लेकर बरेली तक तराई बेल्ट में कांग्रेस की जड़ें खुदेंगी और भाजपा को ताकत मिलेगी। बता दें कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में ही कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन ने चौंकाया था।

भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा की उन सीटों पर फोकस किया है, जहां पार्टी अब तक कमजोर स्थिति में रही है। 80 से अधिक विधानसभा सीटों को चिन्हित करके विशेष कार्ययोजना बनायी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में राज्यसभा व विधान परिषद सदस्यों को लगाया गया है। बाहरी नेताओं को जोडऩे की कोशिशें भी जारी है। वर्ष- 2022 में 300 प्लस सीटों का आकंड़ा पाने के लिए जातीय समीकरण में फिट बैठने वाले अन्य दलों के स्थानीय नेताओं से निरंतर संपर्क साधा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि करीब एक दर्जन बड़े नाम भाजपा नेतृत्व के संपर्क में है। उनकी ज्वाइनिंग उचित समय पर करायी जाएगी।7

मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत : जितिन प्रसाद द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, जितिन के आने से प्रदेश में भाजपा को मजबूती मिलेगी।

केंद्र के नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब

नए दिशा- निर्देशों का पालन करने का करेंगे हर संभव प्रयास

नई दिल्ली । केंद्र सरकार की नोटिस पर जवाब देते हुए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर ने बताया है कि नए आइटी नियमों के अनुरूप मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस संबंध में और जानकारियां एक हफ्ते के भीतर सरकार से साझा की जाएंगी। आधिकारिक सूत्र के अनुसार, ट्विटर ने सरकार की तरफ से पांच जून को भेजे गए अंतिम नोटिस के जवाब में कहा है कि वह नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है। सूत्र का कहना है कि ट्विटर ने इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय को यह जवाब सात जून को भेजा है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नई गाइडलाइन के अनुपालन का हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस दिशा में होने वाली प्रगति से सरकार को अवगत कराया जाएगा। भारत सरकार के साथ हमारा रचनात्मक संवाद जारी रहेगा।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने पंजाबी रैपर जैजी-बी, सिडनी स्थित हिपहाप कलाकार एल-फ्रेश द लायन और दो अन्य लोगों का अकाउंट ब्लाक कर दिया। इन दोनों कलाकारों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की पुष्टि की कि भारत में उनका ट्विटर अकाउंट ब्लाक कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हुए ट्विटर भारत सरकार के नए आइटी नियमों को मानने में ना-नुकर करता रहा है। जसविंदर सिंह बैंस उर्फ जैजी-बी ने पिछले साल दिसंबर में सिंघु बार्डर पर सरकार के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों का समर्थन किया था। सुखदीप सिंह भोगल को एल-फ्रेश द लायन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में ट्वीट किया था।

पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी।

मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मऊ (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर मऊ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 24 करोड़ के संपत्ति को कुकु किया। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित की गई लगभग 24 करोड़ रुपये की भूमि को जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। इस दौरान जिला प्रशासन ने डुग्गी पिटवाकर सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी।

जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया

जिला प्रशासन का मानना है कि मुख्तार अंसारी ने अपराधिक दुनिया की कमाई से यह संपत्ति अपनी मां के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी की मां ने उसके दोनों बेटे अब्बास और उमर के नाम से वसीयत करवाई थी।

राजनीति | पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदरूनी मसलों पर हुई चर्चा

शुभेंदु ने पीएम मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और नंदीग्राम सीट से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात 45 मिनट तक चली।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। राज्य में 40 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राज्य में यह हिंसा खत्म होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के मुलाकात की थी।

पीएम मोदी से मिलने के बाद श्री अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पश्चिम बंगाल और कई अन्य विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनसे मेरी लगभग 45 मिनट विस्तृत बातचीत हुई। बाद में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक से अपनी मुलाकात के दौरान राज्य के हालात से उन्हें अवगत कराया और कहा कि राजनीतिक हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अधिकारी ने बाद में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की।

संक्रमण पर जीतः इजरायल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क-फ्री देश बन जाएगा, 20 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था कोरोना टीकाकरण

इजराइल। इजरायल कोरोनाकाल में दुनिया का पहला मास्क-फ्री देश बन जाएगा। यहां बंद स्थानों में मास्क लगाने का नियम 15 जून से खत्म होगा। इसकी घोषणा इजरायल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने की।देश में पहले ही बाहर मास्क लगाने का नियम खत्म किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री एडलस्टीन ने कहा, 'अगर आगे संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ा तो पाबंदियां पूरी तरह से हटा ली जाएंगी।' इजरायल में भीड़ पर रोक और आपसी दूरी जैसी ज्यादातर पाबंदियां एक जून से हटा दी गई थीं। हालांकि, विदेश यात्रा से जुड़े ज्यादातर प्रतिबंध अभी नहीं हटाए गए हैं। जैसे नौ देशों की यात्राओं पर अब भी प्रतिबंध है। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारेंटाइन का नियम है। उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। उधर, इजरायल में 12 से 15 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इजरायल में कोरोना टीकाकरण अभियान 20 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। उसके बाद टीकाकरण के लिए आयु का बंधन कम किया जाता रहा।

ट्रक से कुचलकर कत्लः कनाडा में पाकिस्तान मूल के चार लोगों की हत्या

सिटी ऑफ लंदन । कनाडा में पाकिस्तान मूल के चार लोगों की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस परिवार में अब सिर्फ एक 9 साल का लड़का बचा है। मारे गए लोगों में एक डॉक्टर, उनकी पत्नी, मां और 15 साल की बेटी शामिल है। हत्या के आरोप में एक कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा- पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया बहुत तेजी और खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी घटना पर अफसोस जाहिर किया।

क्या है मामला

घटना टोरंटो से करीब 200 किलोमीटर दूर सिटी ऑफ लंदन शहर की है। यहां मिलीजुली आबादी है। जानकारी के मुताबिक, इस क्षेत्र का हर पांचवा नागरिक गैर कनाडाई मूल का है। अरब देशों के नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके बाद दक्षिण एशियाई लोग हैं। मामला रात करीब आठ बजे का है। पाकिस्तानी मूल का यह परिवार सड़क के किनारे बने लिंक रोड पर टहलने निकला था। इसी दौरान काले रंग का एक मिनी ट्रक उनकी तरफ आया और उसने इन चारों लोगों को रौंद दिया। पुलिस ने इसे हत्या का मामला करार दिया।

बौद्ध भिक्षुओं के शरण में रूसी वैज्ञानिकः तिब्बती बौद्ध भिक्षु बताएंगे अंतरिक्ष के सुखद सफर के तरीके

मॉस्को। रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इन दिनों तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की शरण में हैं, पर मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए कि वे कैसे हफ्तों तक अर्ध सुप्तावस्था में रह पाते हैं, गहन ध्यान की स्थिति कैसे लगाते हैं और वापस सामान्य अवस्था में किस तरह आते हैं। उनकी इन प्राचीन पद्धतियों का ज्ञान भविष्य में लंबी दूरी के अंतरिक्ष मिशन में यात्रियों के काम आएगा। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 100 तिब्बती भिक्षुओं पर यह अध्ययन कर रहे हैं। लंबी दूरी के स्पेस मिशन के प्रमुख और मार्स-500 अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रो. युरी बबयेव के मुताबिक भिक्षुओं द्वारा रखी जाने वाली शीतनिद्रा की स्थिति मंगल जैसे मिशन के दौरान महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रो. बबयेव की टीम खासतौर पर टुकडम (मरणोपरांत ध्यान) जैसे दावों का अध्ययन कर रही है। इसमें भिक्षुओं को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है, इसके बावजूद वे हफ्तों तक बिना किसी क्षय के सीधे बैठे रहते हैं। यानि इतने दिन बाद भी उनके शरीर में मृत जैसी कोई दुर्गंध या अन्य लक्षण नहीं दिखता। इसके अलावा चेतना की बदली हुई अवस्थाओं का इस्तेमाल हमारे लिए यह बहुत कारगर है, क्योंकि इसकी मदद से मेटाबॉलिज्म की गति बदली जा सकती है। इन अवस्थाओं को कई घंटों के ध्यान, एकाकीपन और मंत्रोच्चार की मदद से हासिल किया जाता है। इनसे गहरी एकाग्रता मिलती है।

कोरोना को लेकर चीन का लीपापोती अभियान जारी

- **डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा- नमूनों को कर रहा नष्ट**

वाशिंगटन। कोरोना वायरस के वुहान लैब से लीक होने को लेकर बढ़ रही विश्वसनीयता के बीच चीन का लीपापोती अभियान भी जोरों पर चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सलाहकार बोर्ड के सदस्य जेमी मेटजल ने फाक्स न्यूज को बताया कि चीनी प्रशासन नमूनों को नष्ट कर रहा है और रिकार्ड को छिपाने में लगा हुआ है। अपने विज्ञानियों को झूठा आदेश दे रहा है और मूलभूत सवाल पूछने वाले अपने नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाल रहा है। इसने आगे बताया कि चीन कथित तौर पर अगले पांच वर्षों में दर्जनों जैव सुरक्षा स्तर तीन प्रयोगशाला और एक जैव सुरक्षा स्तर चार प्रयोगशाला बनाने की योजना बना

रहा है, क्योंकि जांचकर्ता इस संभावना पर नजर डालते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान प्रयोगशाला से लीक हो सकता है।

संदेह के घेरे में घिरता जा रहा चीन

मेटजल ने कहा कि चीन खुद को जितना पाक साफ दिखाना चाहता है, वह उतना ही संदेह के घेरे में घिरता जा रहा है। हम चीन को यह फैसला करने का अधिकार नहीं दे सकते कि इस सदी की सबसे भयंकर महामारी को लेकर हमें जांच करनी चाहिए या नहीं। डब्ल्यूएचओ के सलाहकार ने कहा कि महामारी के संबंध में पूरी जांच को लेकर हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

वुहान लैब से लीक हुआ था वायरस

अमेरिका सरकार की राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने 2020 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान प्रयोगशाला से लीक हुआ है। वाल स्ट्रीट जर्नल ने गोपनीय दस्तावेज तक पहुंच रखने वाले लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है। कैलिफोर्निया स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने मई 2020 में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इसने वुहान लैब से वायरस लीक होने की बात करते हुए आगे जांच की जरूरत बताई थी। अमेरिकी प्रयोगशाला ने सार्स-सीओवी-2 वायरस के जीनोम विश्लेषण के जरिये यह निष्कर्ष निकाला था।

अमेरिका भारत को दे वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक, महामारी से लड़ने में करे हर संभव मदद : ब्रेड

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रेड वेन्स्ट्रप ने कहा है कि भारत अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार है। इसलिए अमेरिका को भारत की महामारी से लड़ने में हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से अपील की है कि भारत को इस महामारी पर विजय पाने के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ऐसे समय में जबकि हम अपने दोस्तों और साझेदारों पर विचार कर रहे हों जरूरी ये भी है कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और नवाचारों की रक्षा की जाए। ब्रेड ने इस बात पर खासा जोर दिया हे कि भारत को इस महामारी से उबरने के लिए अमेरिकी मदद की सख्त जरूरत है। हमारे पास इस बात का पूरा अवसर है कि हम वहां पर और पूरी दुनिया में जहां भी हमारी सख्त जरूरत है, कोविड वैक्सीन की सप्लाई कर उनकी मदद कर सकें।

ब्रेड ने अमेरिका की मदद के बाबत एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बाते कही हैं। उनका कहना है अमेरिका ने कारगर, सुरक्षित वैक्सीन को रिकॉर्ड समय में तेजी से भेजा है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी सरकार को देश में हो रहे शोध को भी सुरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में

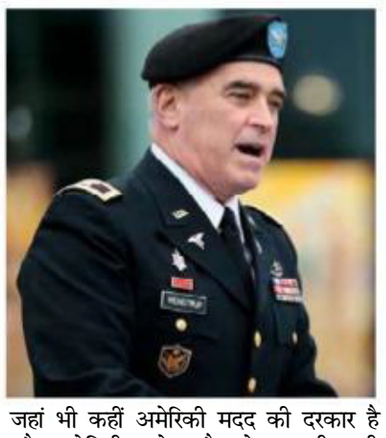

जहां भी कहीं अमेरिकी मदद की दरकार है और अमेरिकी साझेदार है, को मदद दी जानी चाहिए। को से जानी चाहिए।

एक अन्य सदस्य जिम कोस्टा ने कहा है कि भारत लगातार कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने मित्र राष्ट्रों और सहयोगियों को जल्द से जल्द मदद दें। ये मदद वहां पर वैक्सीन की सप्लाई कर की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व को पुराने रूप में वापस आने के लिए सभी देशों के सहयोग की दरकार है। कोई भी एक देश अकेले दम पर इससे नहीं निपट सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के करीब दर्जन भर सदस्यों और सांसदों ने अमेरिकी सरकार से ये अपील की है कि वो भारत में हर संभव मदद पहुंचाए। आपको बता दें कि भारत में फरवरी से शुरू हुई कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लाखों की सख्यों में लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरी लहर में न सिर्फ भारत में रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में बेतहाशा तेजी हुई बल्कि संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ा है।

हालांकि मौजूदा समय में दूसरी लहर का चरम स्तर अब जा चुका है और नए मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अब रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन भारत इस महामारी पर काबू पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है।

सूचना मंत्री ने कहा- भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता रद करने का पर्याप्त आधार

एंटीगुआ। एंटीगुआ के सूचना मंत्री मेलफोर्ड निकोलस ने कहा है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने जब एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, तो उसका नाम किसी भी एजेंसी में नहीं आया था, जिससे यह प्रमाणित होता कि उस पर कोई आरोप तो नहीं है। बहरहाल अब हम उसकी नागरिकता रद करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए चोकसी द्वारा की गई फर्जी घोषणा और कोर्ट में गलत तरीके से चुनौती देने को आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, नागरिकता लेने के दौरान चोकसी द्वारा की गई फर्जी घोषणा की उस पर कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है।

उल्लेखनीय है डोमिनिका के प्रधान मंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने चोकसी को भारतीय नागरिक करार दिया और कहा कि अदालतें तय करेंगी कि भगोड़े का क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चोकसी के अधिकारों की रक्षा करेगी क्योंकि वह मुकदमा चलने का इंतजार कर रहा है।

भगोड़ा चोकसी पीएनबी में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछितः उल्लेखनीय है चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था। उसे डोमिनिका में पकड़ा गया था। प्रत्यर्पण से बचने के संभावित प्रयास में एंटीगुआ और बारबुडा से कथित रूप से भागने के बाद डोमिनिका में पुलिस ने उस पर अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया था। 62 वर्षीय भगोड़ा चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित है।

पाकिस्तान में हुए रेल हादसे में अबतक 62 की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोमवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई। गौरतलब है की सोमवार को कराची से सरगोधा जा रही 'मिल्लत एक्सप्रेस' पटरी से उतर कर बगल वाले ट्रैक पर जा पहुंची थी। इससे रावलपिंडी से कराची आ रही 'सर सैयद एक्सप्रेस' उससे टकरा गई। यह हादसा सिंध के घोटकी जिले के ढरकी शहर के पास हुआ था।27 घंटों तक चला राहत कार्य

एक न्यूज चैनल से बातचीत में पाकिस्तान रेलवे के संभागीय अधीक्षक तारिक लतीफ के हवाले से बताया कि, 27 घंटो के बाद अब राहत कार्य पूरा हो गया है और अप और डाउन दोनों ट्रैकों पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। वहीं पाकिस्तान के एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग ज्वाइंट टूटने के कारण ये हादसा हुआ है।

अत्यधिक संक्रामक है डेल्टा वैरिएंटः चिंतित बाइडन का युवाओं के वैक्सीनेशन पर जोर, कहा-

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 का यह स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है। ब्रिटेन में यह वैरिएंट 12 से 20 वर्ष के आयुवर्ग को तेजी से अपने चपेट में ले रहा है। यदि आप युवा हैं और अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो समय आ गया है। खुद को और अपने परिजनों को बचाने का यह सबसे बढ़िया तरीका है।

बुधवार सुबह अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन्स

हॉपकिन्स ने वैश्विक संक्रमण का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार अब तक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 173,887,864 हो गया है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा है। महामारी के कारण सबसे बुरा हाल अमेरिका का है।

हालांकि यहां वैक्सीनेशन तेजी से होने के कारण अब जाकर हालात पर नियंत्रण हुआ है। अब तक यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,390,694 और मरनेवालों की संख्या 598,323 है।

ब्रिटेन में 12-20 वर्ष का आयुवर्ग है प्रभावित

नींद में गजराज...

चीन के जिन्निंग जिला के पास शिन्यांग के जंगल में सुस्ताता थका-हारा जंगली हाथियों का एक समूह। देश में प्रसिद्धि पा चुका हाथियों का दल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्यात हो गया है। 15 हाथियों का दल अपना जंगली प्रवास छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके, इन दिनों नये ठिकाने की तलाश में निकला हुआ है।

गुतेरस का संयुक्त राष्ट्र का दोबारा महासचिव बनना तय, सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव किया मंजूर

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतेरस के 18 जून को दोबारा इस विश्व निकाय के प्रमुख बनने का रास्ता साफ हो गया है। शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के लगातार दूसरी बार पांच साल के लिए महासचिव बनाने का प्रस्ताव निर्विरोध रूप से मंजूर हो गया है।

उनका दूसरा कार्यकाल एक जनवरी, 2022 से शुरू होना है। भारत ने यह प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जाहिर की है। 15 देशों की सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक बैठक करके 193 सदस्यीय महासभा के लिए दूसरी बार गुतेरस को महासचिव बनाए जाने की सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में एस्टोनिया के राजदूत और जून महीने में परिषद के

अध्यक्ष वेन जर्गुसन ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख के पद के लिए 72 वर्षीय गुतेरस के नाम की सिफारिश की है। गुतेरस का नया कार्यकाल एक जनवरी, 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2026 तक चलेगा।

इस फैसले के बाद गुतेरस ने भी खुशी जताते हुए कहा कि वह बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वह उनमें दोबारा विश्वास जताने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बेहद आभारी हैं। वहीं, जर्गुसन ने कहा कि गुतेरस के महासभा में पुनर्निर्वाचन के लिए मतदान 18 जून को होगा। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट करके कहा, 'भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अंगीकार करने का समर्थन करता है।'

रूस की अमेरिका को दो टूकः प्रतिबंध हटें वरना स्पेस स्टेशन से अलग होंगे

ढेरों रॉकेट तैयार लेकिन अंतरिक्ष नहीं भेज पा रहे

मास्को। रूस ने अमेरिका से कहा है कि अगर स्पेस सेक्टर में लगे प्रतिबंध जल्द नहीं हटाए गए तो वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से खुद को अलग कर लेगा। रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्कोमॉस के प्रमुख दिमित्री रोजोजिन ने यह बयान दिया है। जबकि कुछ ही दिन बाद जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। रोजोजिन ने कहा, 'हमारे पास ढेरों रॉकेट तैयार हैं। लेकिन प्रतिबंधों के चलते ह्म उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भेज पा रहे। इससे स्पेस सेक्टर के व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। अंतरिक्ष यान के लिए एक विशिष्ट माइक्रोचिप सेट

की कमी है। प्रतिबंधों के कारण इसे खरीदने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है।' दरअसल, जिन प्रतिबंधों की बात रोजोजिन कर रहे हैं, वे 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में छिड़े संघर्ष के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लगाए थे

कोरोना दुनिया में: बीते दिन 3.59 लाख केस, 10,219 की मौत; 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की तैयारी में फाइजर

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। कुछ देशों में कोरोना की लहर कमजोर पड़ी है, तो कुछ देशों में संक्रमितों के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में 3 लाख 59 हजार 127 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 10,219 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई।

उधर, फाइजर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी ने हजारों वॉलेंटियर्स का इंतजाम कर लिया है। ट्रायल अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन में किए जाएंगे। शुरुआती ट्रायल में वॉलेंटियर्स को कम मात्रा में डोज दी जाएगी।

12 से 15 साल के बच्चों

को दी जा रही वैक्सीन

अमेरिका में फेडरल रेगुलेटर्स ने पिछले महीने ही 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। फाइजर की वैक्सीन को शुरुआत में 16 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों पर इस्तेमाल के लिए इजाजत दी गई थी।

ब्राजील में नए संक्रमितों का आंकड़ा 50 हजार के पार

ब्राजील में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते दिन यहां 52,448 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई।

इससे पहले नए संक्रमितों का आंकड़ा 30 हजार तक पहुंच गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी ब्राजील में ही रिकॉर्ड की गई। यहां पिछले 24 घंटे में 2,693 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई।

सबसे ज्यादा मामले भारत में आए

दुनिया में रोजाना केसों के मामले में भारत टॉप पर है। यहां मंगलवार को 91,227 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मौतों की बात करें, तो बीते दिन ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हुईं। यहां पिछले 24 घंटे में 2,213 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई।

अब तक 17.47 करोड़ केस

दुनिया में अब तक 17.47 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 37.62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15.84 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.27 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.27 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 85,781 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

केजरीवाल ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर लोगों को वैक्सीन लगावाने के लिए प्रोत्साहित किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में जहां वोट, वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लगावाने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस मुहिम से लोग बहुत खुश हैं। हमने घर से सेंटर तक आने-जाने के लिए ई-रिक्शे का भी इंतजाम किया है। जिस तरह, मतदान से पहले बीएलओ घर-घर जाकर पर्ची देते हैं, उसी तरह वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट की पर्ची दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह की अफवाहें फैली हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी हम सब की है। सीएम ने अपने देश के चुनाव के प्रशासनिक ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि अगर हम अपने चुनावी ढांचे का पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं, तो दो से तीन महीने में सबको वैक्सीन लगा सकते हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में जहां वोट, वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को आगे बढ़ कर वैक्सीन लगावाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक नए किस्म का प्रयोग किया जा रहा है। हमने दिल्ली में देखा है कि 45 साल की उम्र से उपर के लगभग 50 फीसद लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी भी 50 फीसद लोग वैक्सीनेशन से बचे हैं। दिल्ली में करीब 57 लाख लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं और इसमें से करीब 27-28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और करीब 30 लाख लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर अधिक संख्या में लोग नहीं आ रहे थे। इसलिए हमें लगा कि अब घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए निमंत्रित करना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए। इसी के मद्देनजर यह नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का जहां वोट, वहीं वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोग जहां पर वोट डालने जाते हैं, वहीं पर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। पोलिंग स्टेशन को ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है।

दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन व्यवस्था से गई ज्यादा लोगों की जानः आदेश गुप्ता

नई दिल्ली । भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के बजाय होम आइसोलेशन में रखा जिससे यहां संक्रमण बढ़ा। समय पर इलाज नहीं मिलने से हजारों लोगों की जान चली गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राजधानी में लगभग 70 फीसद मकान 100 गज या इससे भी छोटे भी छोटे हैं।

अधिकांश मकान में एक ही शौचालय व स्नानघर है, इसलिए किसी कोरोना संक्रमित का घर में रहने से परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हुए। इस तरह से संक्रमण फैलता चला गया। यदि संक्रमित व्यक्ति की शुरू में पहचान करके उसे अस्पताल या कोरोना केयर सेंटर में भर्ती किया जाता तो इतनी संख्या में लोगों की मौत नहीं होती। **सरकार पर लगा लापरवाह होने का आरोप-** प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा विश्व में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या 455 है। भारत में 234 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 30 मई तक के आंकड़ों को देखें, तो दिल्ली में 1207 लोगों की जान गई है। दिल्ली के लोगों के लिए खरीदे गए आक्सीमीटर व अन्य उपकरणों का दूसरे राज्यों में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से पहली लहर के दौरान बनाए गए अस्थायी कोरोना केयर सेंटर तोड़ दिए गए थे। दूसरी लहर आने पर इन्हें बनाने का फिर से दिखावा किया गया।

कोरोना केयर सेंटर में न तो डॉक्टर थे और न ही जरूरी उपकरण। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन सेंटर बनाने, आक्सीमीटर और अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरणों के खरीद में, कंटनमेंट जोन बनाने में और सिविल डिफेंस भर्ती में गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मोहल्ला क्लीनिक में कोरोना केयर सेंटर और टीकाकरण केंद्र क्यों नहीं बनाए गए।

इधर, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को ही रिपोर्ट दी थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की होम आइसोलेशन व्यवस्था प्रभावी नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना से मरने वालों में 44 फीसद मरीज ऐसे थे जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। सरकार कोरोना की जांच व कोरोना से मरने वालों के आंकड़ें छिपा रही है। सरकार के अनुसार अप्रैल व मई में कुल 13201 लोगों की मौत हुई जबकि नगर निगम के अनुसार यह संख्या 34750 है। मुआवजा न देना पड़े इसलिए मृतकों की सही संख्या नहीं बताई जा रही है।

अधिकारी घर-घर जाकर लाडली योजना के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करें : राजेन्द्र पाल गौतम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय सहायता एवं पेंशन योजनाओं के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और सभी प्रकार की अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं और पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्कीम के तहत लंबित मामलों को तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से

जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अखबारों में बार-बार सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी लाभार्थी योजना का मैंच्योरिटी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

समाज कल्याण मंत्री ने महिलाओं को दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों के लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि विभाग संबंधित बैंक से जीवन प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित करें, ताकि असल लाभार्थियों को लाभ मिल पाए और धोखाधड़ी करने वालों से जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जा सके। लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लाभार्थियों से संपर्क करके जरूरी दस्तावेज और कागजात लेकर मामले का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अपने दोनों विभागों की विभिन्न पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाओं को सुचारू और व्यवस्थित रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी कर हर प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

महामारी ने स्कूली शिक्षा के बारे फिर से सोचने और कुछ नया अपनाने का मौका दिया : सिसोदिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने 2021 में आयोजित होने वाले एजुकेशन वर्किंग ग्रुप इनिशिएटिव में भागीदारी के लिए ग्वेरैंड-हर्मेस फाउंडेशन फॉर पीस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिससे शिक्षक और छात्र स्वतंत्र रूप से भयमुक्त वातावरण में अपने विचारों को साझा कर शिक्षण की पुरानी पद्धतियों को बदल सके। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जी20 इंटरफेथ फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर शेर्टो गिल के साथ पहली ऑनलाइन वर्कशॉप की शुरूआत की। उन्होंने कहा, महामारी के समय में हमारे शिक्षक और छात्र बहुत से मुश्किलों से गुजरे हैं, इससे बाहर निकलने में हम उनका साथ देना चाहते हैं। हम अपने शिक्षकों और उनके छात्रों को एक मंच प्रदान करना चाहते है जहां वो शिक्षण गतिविधियों को दोबारा शुरू करने से पहले खुला संवाद कर सके। सिसोदिया ने कहा कि, महामारी ने हमें स्कूली शिक्षा पर फिर से सोचने और कुछ नया अपनाने का मौका दिया है। हमें यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम तुरंत पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं या क्या हम शिक्षकों और छात्रों को एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने के लिए मौका देना चाहते हैं। हमारे लिए स्कूलों को फिर से खोलना सिर्फ किताबें खोलने भर नहीं है; बल्कि दिल और दिमाग का खुलना ज्यादा जरूरी है ताकि शिक्षक और छात्र एक दूसरे से जुड़ सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्कूल और स्कूली शिक्षा अब पहले की तरह समान नहीं हो सकती हैं अब उनमें बदलाव लाने और उन्हें विकसित करने की जरूरत है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षकों के लिए अपने छात्रों के साथ फिर से जुड़ना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को पिछले कुछ महीनों में जिन मुश्किलों के कारण तनाव हुआ है, अब उन्हें न केवल अपने दुख और तनाव से उबरने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, बल्कि अपने छात्रों का भी सपोर्ट करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि महामारी में छात्र भी समान रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने छात्रों की कॉउंसलिंग करने के लिए खुद को तैयार कर सके, यदि छात्र किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें और उन्हें एक ऐसी स्थिति में आने में मदद करें जहां वे शिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हों। दिल्ली सरकार का जी20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहल ए टाइम टू हील-हाउ एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट टू हीलिंग एंड वेल-बीइंगः ए ग्लोबल लिसनिंग इनिशिएटिव संस्थान के साथ काम करेगी। जीएचएफपी के साथ सहयोग के पहले चरण में, विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली सरकार के मेंटर शिक्षकों के एक छोटे समूह के साथ तीन दिवसीय सत्र आयोजित करेगी। इसके बाद, मेंटर शिक्षक प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षकों के साथ समान सत्र आयोजित करेंगे। ये दोनों शिक्षक अपने स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अपने साथी शिक्षकों की मदद करेंगे। वर्कशॉप में दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय और शिक्षा निदेशक के प्रधान सलाहकार शैलेंद्र शर्मा ने भी भाग लिया।

हर्पीज सिम्पलेक्स वायरस कोरोना मरीजों के लिए है सबसे ज्यादा खतरनाक

गाजियाबाद, (एजेंसी)। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के बाद ब्लैक, व्हाइट और यलो फंगस के बाद नया वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ डॉक्टर का दावा है कि देश में पहला हर्पीज सिम्पलेक्स वायरस गाजियाबाद के एक मरीज में मिला है। यही नहीं, डॉक्टर ने इसे बेहद खतरनाक भी बताया है। यह जिनकी इम्युनिटी कम रहती है या फिर वह किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें ये वायरस अपना शिकार बनाता है। इसका इलाज भी काफी महंगा है।

गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि गाजियाबाद में देश का पहला हर्पीज सिंपलेक्स वायरस पाया गया है, जोकि मरीज की नाक में पाया गया है। यह बेहद ही खतरनाक है। अगर इलाज में देरी की जाती है, तो यह कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक हो सकता है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह वायरस जिनकी इम्युनिटी कमजोर होती है या फिर दूसरी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनके लिए यह ज्यादा घातक है। डॉक्टर बीपी त्यागी के मुताबिक, गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले विवेक त्यागी को यह वायरस हुआ है, जिसका इलाज लगातार हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि इसका इलाज भी बेहद महंगा होता है। वैसे इस बीमारी की दवाइयां हमारे पास हैं, इसलिए विवेक का इलाज संभव है। इसके साथ डॉक्टर ने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि जो कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं उन लोगों को इस तरह की बीमारी होने का पूरा खतरा बना हुआ है।

डीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर मांगे सुझाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संरक्षण नियमों के साथ हरा-भरा पर्यावरण, उज्ज्वल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ईंधनों के साथ परिवहन की तेज रफ्तार आदि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 (एमपीडी) के मसौदे के अहम विषय हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मसौदा एमपीडी 2041 को प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उस पर लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं।

मसौदा योजना में कहा गया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भारत की आजादी के 75वें साल में जारी किया गया है। भारत 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और उसका विकास पथ तेजी से शहरों से परिभाषित हो रहा है जो जीडीपी में 60 फीसदी का योगदान देते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार 2014 में नियोजित शहरी विकास के वास्ते एक समग्र कार्यक्रम की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शहरी विकास पर अधिक ध्यान देने लगी है, जिसका लक्ष्य समावेशी, सहकारी एवं सतत पहल के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तनशील बदलाव लाना है। इसमें जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है वे पर्यावरण, जल, महत्वपूर्ण संसाधन, गतिशीलता, आवास, पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्थल, धरोहर संपदा, आर्थिक संभावना, निगरानी एवं मूल्यांकन हैं।

दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को मिला तीन माह का एक्सटेंशन, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है। 7 जून को एक्सटेंशन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने इस आदेश की सराहना की है। डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी, डीन ऑफ कॉलेजिज डॉ बलराम पाणी व रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता का धन्यवाद किया है। डीटीए प्रभारी डॉ हंसराज सुमन ने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर डीटीए का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुये कहा है कि इन कॉलेजों में शिक्षकों

की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही पदोन्नति पूर्ण होगी उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो कर सकता है।

उन्होंने दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि 15 जनवरी 2021 के कार्यालय पत्र फिर 29 जनवरी 2021 के पत्र के संदर्भ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में नामित गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को तीन महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी। उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ रचनात्मक संवाद के कारण यह संभव हो पाया है। धीरे-धीरे 28 कॉलेजों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। डीटीए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षाविद ,पत्रकार ,डॉक्टर ,संस्कृतकर्मी के अलावा अकादमिक जीवन में योगदान देने वालों का ही नाम भेजे ताकि उन कॉलेजों को स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व मिल सके इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा।

उत्तर रेलवे के अस्पताल में शुरू हुआ आक्सीजन उत्पादन, अब नहीं होगी किल्लत

नई दिल्ली । कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान चली गई। पूरे देश में आक्सीजन की कमी थी, लेकिन दिल्ली में स्थिति ज्यादा भयावह हो गई थी। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में आक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है। इससे अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को आक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने में आसानी होगी।

रेल मंत्रालय ने अस्पतालों को आक्सीजन के मामले में आत्म निर्भर बनाने का लक्षय रखा है। इसके तहत 84 रेलवे अस्पतालों में आक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस काम में किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए महाप्रबंधक को दो करोड़ रुपये तक के खर्च को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। नई दिल्ली स्थित अस्पताल में संयंत्र बनकर तैयार हो गया है और बुधवार को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल और डीएफसीसी के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने इसका उद्घाटन किया है।

जेल में भी एक्सरसाइज कर रहा है सुशील कुमार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इसका ताजा मामला सुशील पहलवान का देखने को मिल रहा है। जेल की सलाखों में पहुंचने के जहां एक तरफ उसे मनमर्जी का खाना-पीना नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ उसने शरीरिक व्यायाम करने के लिए बिसलेरी की बड़ी बोतलों में पानी भरकर उसके डंबल बना लिए हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि सुशील ने एक डंडे को रॉड का रूप देकर उसके दोनों किनारों पर बोतले बांधी हुई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि डाइट को लेकर अदालत ने जेल प्रशासन जवाब मांगा था, उसका जवाब दे दिया गया है। अदालत जैसा आदेश जारी करेगी उस पर अमल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुशील पहलवान क्वारंटाइन सेल में एक-एक दिन मुश्किल से काट रहा है। वह कई बार अपनी सेल के बाहर सुरक्षा में लगे वार्डर से पूछ चुका है कि आमने-सामने की मुलाकात कब शुरू होगी ताकि उसे मिलने के लिए लोग आ सकें। वार्डर ने इस बात की जानकारी अपने उप-अधीक्षक को दी। बताया गया कि सुशील से फोन पर ही अपने परिजनों से बात करने की इजाजत दी गई है। वह दिन में भी गुमसुम रहता है। सूत्रों का कहना है कि सुशील पहलवान ने एक वार्डर से बिसलरी की खाली बोतलों में पानी भर कर मंगवाया

था और उनको एक छोटे डंडे से बांध कर डंबल बना लिए और इन्हें वह शरीरिक व्यायाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। व्यायाम करने के बाद वह कैंटीन से दूध मंगवाता है। फिलहाल उसके अधिवक्ता की तरफ से अदालत में खाने-पीने को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी उसका जवाब जेल अधिकारियों ने अदालत को सौंप दिया है। सागर धनखंड हत्याकांड में इन दिनों सुशील पहलवान मंडोली जेल नंबर 15 की सेल में क्वारंटाइन है। उसकी क्वारंटाइन अवधि खत्म होने के बाद उसे सुरक्षा की दृष्टि से तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा।

26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन होगा : गोपाल राय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर आज सभी हरित एजेंसियों/ विभागों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इसमें सभी की विभागों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने वृक्षारोपण कार्य का चल रहे थर्ड पार्टी ऑडिट को जल्द पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस साल वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर सभी हरित एजेंसियों और विभागों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे पौधे लगाने पर अधिक जोर देगी, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

दिल्ली सरकार इसके लिए अभियान भी चलाएगी। साथ ही, इस अभियान के तहत दिल्ली के लोगों को जागरूक कर उन्हें भी इससे भी जोड़ेगी। दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान में इस साल 33 लाख पौधे लगाने का

लक्ष्य रखा है। इसमें लगभग 18 लाख पौधे दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों की तरफ से लगाए जाएंगे। इसमें वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, डीटीसी, शिक्षा, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड आदि विभाग शामिल हैं। 6 लाख पौधे डीडीए की तरफ से दिल्ली में लगाए जाएंगे। एनडीएमसी द्वारा 5 लाख और तीनों एमसीडी द्वारा मिलकर 3 लाख 30 हजार पौधे लगाएं जाएंगे। इसके अलावा, मेट्रो, सीपीडब्ल्यूडी, नॉर्दन रेलवे, एनडीपीएल, दिल्ली कैन्टोमेंट बोर्ड, बीएसईएस आदि के माध्यम से भी पौधे लगाए जाएंगे।

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव भी आयोजित करने जा रही है। उन्होंने वन महोत्सव में सभी संबंधित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और पूरे साल शहर भर में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा है। इस वृहद पौधारोपण अभियान (मेगा प्लांटेशन ड्राइव) में दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, विधायक, गैर सरकारी संगठन और आरडब्ल्यूए शामिल होंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर औषधीय पौधों का मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है। दिल्ली में सरकार की 14 नर्सरी है। कोई भी व्यक्ति हमारी नर्सरी में जा सकता है और मुफ्त में औषधीय पौधे प्राप्त कर सकता है। दिल्ली सरकार की नर्सरी में जो औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, उसमें आंवला, अमरूद, अर्जुन, जामुन, नीम, तुलसी इत्यादि हैं।

संपादकीय

आपदा को अवसर नहीं बना पाए हम

जब कोविड नहीं था, तब बहुत कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा हम बहुत सी चीजों के बारे में या शायद सभी चीजों के बारे में कह सकते हैं। लेकिन निश्चित और निर्विवाद तौर पर वैक्सीन बाजार के बारे में तो यह कहा ही जा सकता है। तब तक इस बाजार में हम सबसे आगे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2019 के आंकड़ों को देखें, तो दुनिया के वैक्सीन बाजार में 28 फीसदी हिस्सेदारी अकेले भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की थी। पता नहीं, बात कितनी सच है, लेकिन यह अक्सर सुनाई देती थी कि पूरी दुनिया का 12 साल का कोई भी बच्चा जिसका पूर्ण टीकाकरण हुआ हो, उसे अपने पूरे जीवन में कभी न कभी सीरम इंस्टीट्यूट का एक टीका तो लगा ही होगा। यानी, वैक्सीन के मामले में इस तरह के नैरेटिव हमारे गौरव-बोध को थपथपाने के लिए मौजूद थे। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा देश की कई और कंपनियां भी वैक्सीन बनाने और निर्यात करने का काम करती हैं। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए, तो दुनिया के वैक्सीन बाजार में भारत की हिस्सेदारी एक तिहाई से कहीं ज्यादा थी। बात सिर्फ 2019 के आंकड़ों की नहीं है। 2020 के अंत तक यही माना जा रहा था कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यहां तक कहा था कि वैक्सीन की जो उत्पादन-क्षमता भारत के पास है, वह दुनिया की एक महत्वपूर्ण संपदा साबित होने वाली है। इन्हीं सबसे उत्साहित होकर भारत ने अपने जनसंपर्क को बढ़ाने का फैसला किया और दिसंबर की शुरुआत में सभी देशों के राजदूतों को एक साथ बुलाकर वैक्सीन की प्रयोगशालाओं व उत्पादन इकाइयों का दौरा करवाया। इस दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के राजदूतों ने भारत की वैक्सीन उत्पादन-क्षमता के लिए कई कसीदे भी गढ़े थे। हम इस बात को लेकर खुश थे कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो सकती हैं, अस्पताल, मरीजों के लिए बिस्तर व स्वास्थ्यकर्मी कम पड़ सकते हैं, वेंटिलेटर का अकाल हो सकता है, ऑक्सीजन जरूरत से काफी कम पड़ सकती है, बहुत सी दवाओं की कमी से उनकी कालाबाजारी हो सकती है, पर वैक्सीन के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। और कुछ न हो, मगर कोविड को मात देने वाला असली ब्रह्मास्त्र तो हमारे पास है ही। साल 2021 के शुरुआती हफ्तों तक यही लग रहा था कि भारत नए झंडे गाड़ने जा रहा है। पहले चरण में सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगने थे। जितने टीके लग रहे थे, उससे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन की खबरें आ रही थीं। कुछ विश्लेषक तो यह भी कह रहे थे कि भारत के स्वास्थ्य तंत्र के पास टीकाकरण की जो क्षमता है, भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता से वह कहीं कम है, इसलिए भारत के पास हमेशा वैक्सीन का सरप्लस स्टॉक रहेगा। शायद इसी तर्क के चलते भारत ने टीकों का निर्यात भी किया, जो इन दिनों काफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। विदेश नीति के बहुत से टीकाकारों ने इस निर्यात को 'वैक्सीन डिप्लोमेसी' बताते हुए इसकी तारीफों के पुल भी बांधे थे।

लेकिन अप्रैल आते-आते ऐसा क्या हुआ कि सारा शीराजा बिखर गया? एक तो उम्र के हिसाब से टीकाकरण की योग्यता को लगातार विस्तार दिया जाने लगा। फिर इसी बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई, जो पहले से कहीं ज्यादा भयावह और संक्रामक थी। लोगों को लगा कि टीकाकरण जल्दी होना चाहिए और वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। सरकारी व निजी अस्पतालों ने टीकाकरण की अपनी क्षमता को बढ़ा दिया, कुछ जगह तो चौबीस घंटे टीकाकरण की सुविधा दे दी गई। जब यह स्थिति आई, तब पता चला कि टीके कम पड़ रहे हैं। सभी राज्यों से टीकों का स्टॉक खत्म होने की खबरें आने लगीं। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी थी? शायद नहीं। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन उत्पादन का दुनिया का सबसे अग्रणी देश भारत कोविड वैक्सीन के मामले में मात खा गया। पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी बिल गेट्स फाउंडेशन से 30 करोड़ डॉलर की मदद लेने के बावजूद अभी तक कोविड वैक्सीन की सिर्फ छह करोड़ खुराक बना पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत सरकार ने इतने का ही ऑर्डर दिया था। यह सच है कि इसके पहले सीरम कभी भारत सरकार के ऑर्डर की मोहताज नहीं रही, वह अपनी वैक्सीन पूरी दुनिया को बेचती रही, पर इस बार तमाम बैंड, बाजा, बारात के बावजूद उसने सेहरा अपने माथे पर सजाने का मौका गंवा दिया। इसकी तुलना अगर हम दुनिया की दूसरी कंपनियों से करें, तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। फाइजर दुनिया की एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी दवा निर्माता कंपनी है, लेकिन वैक्सीन के बाजार में उसकी कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी हाल-फिलहाल में नहीं रही। उसने अब दुनिया भर के देशों से 52 करोड़ वैक्सीन डोज निर्यात करने का समझौता कर लिया है, जिसे वह जल्द ही अमली जामा पहनाने की बात भी कर रही है। कंपनी का दावा है कि इस साल के आखिर तक वह 1.3 अरब वैक्सीन डोज का उत्पादन कर लेगी। स्पूतनिक-वी नाम की वैक्सीन बनाने वाली रूस की कंपनी के दावे भी ऐसे ही हैं। चीन तो कई बार इससे भी बड़े दावे कर चुका है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दवा व वैक्सीन उद्योग में इसके पहले तक कोई अनुभव नहीं था, पर अब वह अमेरिका की सबसे अग्रणी वैक्सीन उत्पादक कंपनी बन चुकी है, जबकि यहां भारत में सबसे अनुभवी कंपनी बेबस दिखाई दे रही है। जिस समय भारत की कामयाबी के हर तरफ चर्चे होने चाहिए थे, उस समय पूरी दुनिया भारत पर तरस खा रही है। और भारत की राज्य सरकारें झोला उठाकर वैक्सीन की खरीदारी के लिए भटकने को मजबूर हैं। इस संकट ने यह भी बता दिया कि भारत की जिन कंपनियों को हम अभी तक दुनिया में सबसे आगे मानते थे, वे दरअसल ऑर्डर मिलने पर उत्पादन करने वाली फैक्टरियां भर हैं। ऐसे उद्योगों से भला यह उम्मीद कैसे की जाए कि वे आपदा को अवसर में बदल सकेंगी?

प्रवीण कुमार सिंह

कितना जायज है सेहत की चिंता पर परीक्षा रद करना, परिस्थिति अनुकूल निर्णय लेना ही उचित

छात्रों की स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर टीकाकरण जैसा कदम सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से भी छात्रों में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसके लिए राज्यों को कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि तय समय में तैयारियां पूरी की जा सकें। तैयारियां चाहे कितनी भी करनी हो, परीक्षा रद करना कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर अगले साल भी स्थिति अनुकूल नहीं रही तो परीक्षा रद करने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सिर्फ सेहत की चिंता पर परीक्षा रद करना सिस्टम की कमजोरी को उजागर करेगा, इसलिए हमारे नीति-नियंताओं को एक मजबूत खाका तैयार करने की जरूरत है।

सीबीएसई ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा रद करने का निर्णय लिया और उसके बाद अब 12वीं की परीक्षा भी आशंकाओं के घेरे में है। इंटरनेट मीडिया के विविध मंचों पर 12वीं के छात्रों का एक बड़ा समूह इस परीक्षा को रद करने का आग्रह कर रहा है। हालांकि अभिभावकों या छात्रों द्वारा परीक्षा को टालने या रद करने की मांग के पीछे स्वास्थ्य जैसी चिंता वाजिब है। कोई अभिभावक नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो।

वैकल्पिक इंतजाम में एक प्रकार की जनरल मार्किंग होगी- लेकिन छात्रों और अभिभावकों का एक समूह परीक्षा आयोजित कराने की वकालत भी कर रहा है। इसमें वे मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने महामारी जैसे कठिन समय में भी परीक्षा की तैयारी की है। ऐसे में परीक्षा रद होने से इन मेधावी छात्रों का सीधे तौर पर नुकसान होता दिख रहा है। अगर परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है तो मूल्यांकन के वैकल्पिक इंतजाम में मेहनती छात्रों की पहचान कैसे होगी? जाहिर है, वैकल्पिक इंतजाम में एक प्रकार की जनरल मार्किंग होगी, जिसमें इन मेधावी छात्रों के लिए भावी जिंदगी में चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

यह आशंका इसलिए भी जायज है क्योंकि 10वीं की परीक्षा के लिए सीबीएसई ने साल भर की परीक्षाओं को आधार बनाया है। प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, यूनिट टेस्ट आदि के आधार पर सीबीएसई ने 10वीं के मूल्यांकन करने की बात कही है। हालांकि सीबीएसई के पास इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी छात्र के लिए पूरा साल एक जैसा नहीं होता। बीमारी के कारण कुछ बच्चे कुछ परीक्षा नहीं दे पाते या किसी पारिवारिक तनाव के चलते किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुछ मेधावी छात्र भी कई कारणों से स्कूल की आंतरिक

परीक्षाओं में गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन छात्रों के एक बड़े समूह के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 10वीं के लिए यह नुकसान तो सहा भी जा सकता है। लेकिन 12वीं के लिए यह नुकसान छात्रों के करियर को झटका दे सकता है। 12वीं की परीक्षा के आधार पर ही विभिन्न कोर्सों में छात्र दाखिला लेते हैं। नीट और आइआइटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में 12वीं की परीक्षा में अंक ही मायने रखते हैं। ये वो परीक्षाएं हैं जो छात्रों के करियर को तय करती हैं और उनकी भावी जिंदगी की दहलीज मानी जाती हैं।

इसका एक दूसरा पक्ष है कि 12वीं की परीक्षा आयोजित न कराने की स्थिति में सीबीएसई स्वाभाविक रूप से स्कूलों से छात्रों की रिपोर्ट मांगेगी, जैसा कि 10वीं जमात के लिए मांगी गई है। ऐसे में यह गौर करने लायक बात है कि इससे स्कूलों की शक्ति बढ़ जाती है। मूल्यांकन की इस वैकल्पिक विधि से स्कूलों के पाले में गेंद चली जाएगी। स्कूल जिस तरह की रिपोर्ट सीबीएसई को सौपेंगे, छात्रों का रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आएगा। यही कारण है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं के छात्रों के अभिभावकों को रिजल्ट की चिंता सताने लगी है। इसकी वजह है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद हैं। ऐसे में छात्र न तो स्कूल जा सके हैं और न ही अधिकांश अभिभावक पूरी फीस दे सके हैं। लिहाजा, कुछ स्कूल प्रबंधन ऐसे अभिभावकों से नाराज हैं। इससे अभिभावकों को भय है कि अगर स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों की बेहतर रिपोर्ट नहीं भेजी गई, तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जिस प्रकार से शिक्षा का व्यावसायीकरण हो चला है उससे इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुछ विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों पर पैसे ऐंठने के लिए दबाव बनाया हो।

यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को 10वीं और 12वीं के छात्रोंके रिजल्ट को न रोकने के आदेश पारित करने पड़े। लिहाजा परीक्षा रद करने की बजाय परीक्षा आयोजित कराने वाला विकल्प छात्रों के हित में है। हां, इसमें कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। दरअसल परीक्षा न कराने के पीछे सारा डर संक्रमण के फैलने का है। ऐसे में कुछ सतर्कता और प्रबंधन से इस संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। सीबीएसई के मुताबिक 12वीं की परीक्षा में करीब 14 लाख छात्र शामिल होंगे। इसलिए छात्रों के बीच दूरी बना कर परीक्षा लेने के लिए एक विषय की परीक्षा दो पालियों में ली जाए। दूसरी सतर्कता हो कि सभी छात्रों के लिए होम सेंटर की व्यवस्था हो। इससे छात्रों को सुविधा होगी। संक्रमण से बचाव के लिए यह कदम बेहद कारगर साबित होगा।

इससे इतर, परीक्षा का फार्मेट बदलना भी एक बेहतर विकल्प होगा। कुछ प्रमुख विषयों की ही परीक्षा लेना समझदारी भरा फैसला होगा। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के कुछ मुख्य विषयों की ही परीक्षा होनी चाहिए। इसके आधार पर ही बाकी विषयों का मूल्यांकन किया जाए। प्रश्नों की संख्या को कम कर परीक्षा के समय को कम करना भी अच्छा कदम हो सकता है। परीक्षा आयोजित कराने के मद्देनजर तीन राज्यों- दिल्ली, पंजाब और बंगाल ने परीक्षा से पहले छात्रों का टीकाकरण कराने का सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए। जब छात्रों की स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर ही इतना विमर्श हो रहा है, तो ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।

छात्रों की स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर टीकाकरण जैसा कदम सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से भी छात्रों में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसके लिए राज्यों को कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि तय समय में तैयारियां पूरी की जा सकें। तैयारियां चाहे कितनी भी करनी हो, परीक्षा रद करना कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर अगले साल भी स्थिति अनुकूल नहीं रही तो परीक्षा रद करने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सिर्फ सेहत की चिंता पर परीक्षा रद करना सिस्टम की कमजोरी को उजागर करेगा, इसलिए हमारे नीति-नियंताओं को एक मजबूत खाका तैयार करने की जरूरत है।

टीका नीति की समीक्षा हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर जो तीखी टिप्पणी की है, उसे संदर्भ से काटकर नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने पहले दो फेज में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने और बाद में 18-44 वर्ष उम्र समूह के लोगों से टीके की कीमत चुकाने के लिए कहने की नीति को पहली नजर में मनमाना और बेतुका बताया है। इतना ही नहीं, उसने वैक्सिनेशन की कथित लिबरलाइज्ड पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं की विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। यह भी कहा कि सरकार उठाए गए सवालों की रोशनी में टीकाकरण नीति की फिर से समीक्षा करे और दो हफ्ते में हलफनामा दायर कर अदालत को उसमें किए गए बदलावों की विस्तार से जानकारी दे। शीर्ष अदालत के इस कड़े रुख के पीछे निश्चित रूप से देश में पिछले कुछ समय से टीकाकरण को लेकर देखी जा रही अनिश्चितता और अव्यवस्था की स्थिति का भी हाथ है। न केवल टीके की अलग-अलग कीमतों को लेकर राज्य सरकारें केंद्र से शिकायत करती रही हैं बल्कि टीके की सप्लाई को लेकर भी अनिश्चितता का आलम रहा।

कई राज्यों में बहुत सारे टीका केंद्र तात्कालिक तौर पर बंद करने पड़े तो कई जगह से लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी बिना टीका लगवाए वापस लौटने की नौबत आई। ऐसी शिकायतें भी मिलीं कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों को टीके की सप्लाई हो रही है, लेकिन राज्य सरकारों को उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही। इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर अदालत ने अपने इस आदेश में स्पष्ट किया है कि संविधान में शक्ति और अधिकारों का बंटवारा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियों की वजह से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो न्यायपालिका मूकदर्शक बनी रहेगी। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि कार्यपालिका की समझ पर भरोसा करते हुए कोर्ट को नीतियां निर्धारित करने का काम उस पर छोड़ देना चाहिए।

अदालत ने उस संदर्भ में कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत उसका काम यह देखना है कि बनाई गई नीतियां संविधान द्वारा तय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं और लोगों के जीने के अधिकार की रक्षा करती हैं या नहीं। बहरहाल, अभूतपूर्व चुनौतियों से भरे इस दौर में शासन के विभिन्न अंगों के नेक इरादों पर पूरा भरोसा जताते हुए भी यह कहना जरूरी है कि वे समझदारी के साथ-साथ संयम का भी दामन थामे रहते हुए आगे बढ़ें। जरा सी भी गलतफहमी उनसे ऐसी गलतियां करवा सकती है, जिसकी देशवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक-दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखते हुए और हर कदम पर अपनी गलतियां दुरुस्त करते हुए ही हम इस कठिन दौर से निकल सकते हैं।

जब कोई सरकार अपने लोगों की जान की दुश्मन बन जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का शिकार हुए लोगों की पीड़ा सुनने का समय निकाल लिया, लेकिन इसमें उसे 20 दिन से अधिक का समय लग गया और अभी उसने इस मसले पर दायर याचिका पर केवल बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस भर दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा कि उन लुटे-पिटे-अभागे लोगों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इस कारण मारा-पीटा, लूटा-खदेड़ा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर भाजपा को वोट दिया। भाजपा समर्थकों को मारने-पीटने, उनके घर जलाने और उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करने का सिलसिला चुनाव परिणाम आने वाले दिन तभी शुरू हो गया था, जब यह साफ हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आने जा रही है।

तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित इस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस ने ऐसे व्यवहार किया, जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। वह तृणमूल कार्यकर्ताओं की खुली-नग्न गुंडागर्दी के समक्ष मूक दर्शक बनी रही। इसी कारण उसकी मौजूदगी में हिंसा और लूट का नंगा नाच हुआ। कोई भी यह समझ सकता है कि ऐसा ऊपर से मिले निर्देशों के तहत ही हुआ होगा। यह भी समझा जा सकता है कि कम से कम ऐसे निर्देश चुनाव आयोग ने तो नहीं ही दिए होंगे। फिर किसने दिए होंगे? इसे जानने-समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए और नहीं, क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्ना वाले डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रहे थे, तब ममता बनर्जी कह रही थीं कि बंगाल में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है। बाद में ममता ने इसकी भी कोशिश की राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने न जा सकें। मजबूरी में उन्हें बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा।

राज्यपाल जब हिंसा पीड़ित लोगों के बीच गए तो उन्हें अत्याचार और आतंक की भयावह कहानियों से दो-चार होना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी अपने ही राज्य के लोगों की दारूण दशा देखकर भी नहीं पसीजीं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस आशय की चिट्ठी अवश्य लिखी कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाए। राज्यपाल तो वापस होने से रहे, लेकिन ममता शायद उन लोगों की भी वापसी नहीं चाह रही हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के आतंक से भयभीत होकर असम में शरण लेने को बाध्य हुए हैं-ठीक वैसे ही जैसे एक समय कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने को बाध्य हुए थे।

चूंकि ममता बनर्जी यह दिखा रही हैं कि बंगाल में चहुंओर अमन-चैन है इसलिए हकीकत जानने के लिए असम के उन शिविरों का रुख करना होगा, जहां बंगाल के लोग पलायन करने के बाद शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि कोई अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने को विवश हो, लेकिन देश की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसी प्रतीति बिल्कुल नहीं कराता कि बंगाल में चुनाव बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और उसके चलते हजारों लोग जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर असम जा पहुंचे हैं। इस पर हैरानी नहीं, क्योंकि एक तो ममता कथित तौर पर सेक्युलर नेता हैं और दूसरे, असम पलायन करने को विवश हुए लोग किसी भाजपा शासित राज्य के नागरिक नहीं हैं।

अगर कहीं बंगाल जैसी हिंसा किसी भाजपा शासित राज्य में होती तो आज नहीं, बहुत पहले ही उसकी खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी आ गई होती और अब ऐसे लेख लिखे जा रहे होते कि भारत में फासिस्ट ताकतें किस तरह बेलगाम हो गई हैं? ऐसा नहीं है कि किसी ने बंगाल की चुनाव बाद हिंसा का संज्ञान नहीं लिया। यह काम कई संस्थाओं ने किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा, क्योंकि जब कोई राज्य सरकार ही अपने लोगों की जान की दुश्मन बन जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद अदालतें भी नहीं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने यह पाया कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सब कुछ सही कर दिया है। उसने चुनाव बाद हिंसा पर लगाम लगाने के लिए ममता सरकार की तारीफ भी की और इस हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने की मांग खारिज कर दी। अब यही मांग उस याचिका में की गई है, जिसकी सुनवाई सात जून को होनी है। कायदे से यह याचिका बहुत पहले सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि देर क्यों हो गई? यह देरी इसलिए क्षोभ का विषय है, क्योंकि हमारी अदालतें शाम-देर शाम और यहां तक कि रात को भी कुछ मामले सुन लेती हैं। चंद दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में कालाबाजारी-जमाखोरी के आरोपित नवनीत कालरा के जमानत के मामले की सुनवाई शाम को हुई। कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल की भीषण राजनीतिक हिंसा पर सुनवाई करते समय किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह सभी को जानना चाहिए कि इस हिंसा में 23 लोग मारे गए हैं। चार महिलाओं से दुष्कर्म हुआ है।

ट्विटर, फेसबुक की अमेरिका एवं यूरोप के लिए एक नीति और भारत के लिए दूसरी नीति

जब गणेश परिक्रमा ही संगठन का आधार बन गया तो गणेश (गांधी परिवार) और परिक्रमा करने वाले ही शेष हैं। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना कोई अंग्रेजों के समय नहीं आई। भारतीय राष्ट्रीय चेतना वैदिककाल से विद्यमान है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में धरती माता के यशोगान का वर्णन है। इसी प्रकार वायुपुराण में भारत को अद्वितीय कर्मभूमि बताया गया है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय प्रखर होती है, जब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास होता है। आज देश ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। इसलिए जरूरत इसकी है कि राष्ट्रवाद के रास्ते की बाधाओं को दूर किया जाए। नियति ने यह दायित्व नरेंद्र मोदी को सौंपा है।

जिस देश की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, उसी देश में आज राष्ट्रवाद को गाली बनाने की कोशिश हो रही है। जी हां, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूं। ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में हैं। वैसे तो दुनिया भर में जहां भी राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, उसे एक वर्ग खतरे के रूप में देख रहा है, पर अपने देश में मामला थोड़ा अलग है। यहां इस मुद्दे पर कोई वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो रही है। बस, फैसला सुना दिया गया है, क्योंकि यहां विरोध का आधार सिद्धांत नहीं व्यक्ति है। इस लड़ाई में सबसे आगे वही पार्टी खड़ी है, जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। एक व्यक्ति के खिलाफ तर्कहीन घृणा के बूते अभियान चलाया जा रहा है। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे के भी सोना हो जाने की बात कही जाती है, वैसे ही ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के छूने से सोना भी कोयला हो जाता है। इनकी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री इस सबसे बेपरवाह हाथी की तरह चले जा रहे हैं। हाथी की यह विशेषता होती है कि वह सामने आदर भाव से खड़े लोगों के लिए रुकता नहीं और पीछे से भौंकने वालों को पलटकर कभी देखता नहीं, पर ऐसा लगता है कि पानी सिर के ऊपर जा रहा है। इतनी बड़ी महामारी के समय सरकार की कमियों, असफलताओं, भूलों के प्रति सवाल उठें तो समझ में आता है, पर परपीड़ा से आनंदित होने वालों को आप किसी तर्क से समझा नहीं सकते। आप तर्क दीजिए, वे भावना पर आ जाएंगे। आप भावना की बात कीजिए, वे तर्क के पीछे छिप जाएंगे। तथ्य और सत्य से इन्हें परहेज है। इस वर्ग की सारी बौद्धिक

ताकत का दर्द यह है कि भइया यह टूटता क्यों नहीं है?

सात साल में या कहें कि बीस साल में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पूंजी से कुछ खर्च हुआ है। इससे मोदी से घृणा करने वाला खेमा अति उत्साहित है। उसे रेत में पानी दिख रहा है, पर मरीचिका का पता तो पास जाने पर ही चलता है। इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री और उनका तंत्र ही जिम्मेदार है। आप दोस्त के लिए न रुकें, कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को पहचानकर और जानकर छोड़ देने का खामियाजा तो एक दिन भुगतना ही पड़ता है। दूसरी बात यह कि भारत के नेताओं को पता नहीं कब समझ आएगा कि विदेशी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भारत के खिलाफ था, है और रहेगा। इसमें मोदी विरोध जुड़ने से यह और खरतरनाक हो गया है। विदेशी मीडिया के इस खेमे, लेफ्ट लिबरल मीडिया एवं कथित बुद्धिवादियों और नागर समाज के लोगों की सोच मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति लोहे के सांचे में ढल चुकी है। वे इसे फिर से बनाने के बारे में सोचने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा किया तो सोच में बदलाव करना पड़ सकता है और ऐसा होना उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाएगा। इन लोगों ने अब अपनी लड़ाई विदेशी डिजिटल मीडिया कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया है। मोदी सरकार के ये नए विरोधी हैं। सरकार उनके एकतरफा विमर्श के प्रतिकार के खिलाफ एक कदम बढ़ाती है फिर दो कदम पीछे खींच लेती है। इसलिए इन संस्थानों पर सरकार की बातों का कोई असर नहीं होता।

रामधारी सिंह दिनकर ने सही लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत और सरल हो। क्षमा बहुत अच्छा भाव है, पर सुपात्र के लिए। किसी के दमन की जरूरत नहीं है, पर समानता की मांग से संकोच क्यों? क्यों ऐसा है कि ट्विटर, फेसबुक और दूसरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स की अमेरिका एवं यूरोप के लिए एक नीति है और भारत के लिए दूसरी? सरकार की नीति ने उन्हें महाबली बना दिया है। यह उनकी ताकत नहीं, हमारी कमजोरी है। हमारी ताकत हमारी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और उपभोग क्षमता है। सरकार तय कर ले तो 24 घंटे में इन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके बाद जो होगा, उसकी आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है।

गोस्वामी तुलसी दास ने लिखा है- विनय न मानत जड़धि जल गए तीन दिन बीति, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीति। तो सवाल है कि आज के संदर्भ में भय किसका? देश के कानून का, संविधान का और एक सौ पैंतीस करोड़ भारतवासियों के हित का, क्योंकि राहुल गांधियों, ममता बर्निजयों, शरद पवारों, उद्धव ठाकरों, हेमंत सोरेनों, तेजस्वी और अखिलेश यादवों से कुछ न हो पाएगा। चिट्ठियां लिखने वालों में से ज्यादातर जनतंत्र में सामंतशाही के प्रतीक हैं। रही बात सीताराम येचुरियों की तो वे तो पिनराई विजयन की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में समाहित हो चुके हैं।

भाजपा के वैचारिक विरोध में खड़े होने का माद्दा किसी में था तो कम्युनिस्ट पार्टियों में ही। आखिर 1967 से 2009 तक कांग्रेस की ओर से वैचारिक लड़ाई का मोर्चा तो वामपंथियों ने ही संभाल रखा था। इंदिरा गांधी ने 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद ही समर्थन के एवज में कांग्रेस का सारा बौद्धिक और वैचारिक काम कम्युनिस्टों को आउटसोर्स कर दिया था। इसीलिए कम्युनिस्टों के पराभव के बाद कांग्रेस की एक टांग (वैचारिक) टूट गई। दूसरी टांग (संगठन) का क्षरण भी लगभग उसी समय से शुरू हो गया। यह अलग बात है कि प्रक्रिया पूरी हाल के वर्षों में हुई है। जब गणेश परिक्रमा ही संगठन का आधार बन गया तो गणेश (गांधी परिवार) और परिक्रमा करने वाले ही शेष हैं। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना कोई अंग्रेजों के समय नहीं आई। भारतीय राष्ट्रीय चेतना वैदिककाल से विद्यमान है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में धरती माता के यशोगान का वर्णन है। इसी प्रकार वायुपुराण में भारत को अद्वितीय कर्मभूमि बताया गया है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय प्रखर होती है, जब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास होता है। आज देश ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। इसलिए जरूरत इसकी है कि राष्ट्रवाद के रास्ते की बाधाओं को दूर किया जाए। नियति ने यह दायित्व नरेंद्र मोदी को सौंपा है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लिया गोद

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में न सिर्फ संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि दक्ष मानव संसाधन की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी सांसद व विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को गोद लेकर उसे चमकाने में जुटे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश की चार सीएचसी गोद लेकर सीधा संदेश दिया है कि कोरोना से बच्चों व बड़ों को बचाने के लिए हर हाल में बेहतर इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सीएचसी जंगल कौड़िया व सीएचसी चरगांवा, वाराणसी के सीएचसी हाथी बाजार व अयोध्या में मसौधा स्थित सीएचसी को गोद लिया है। इन चारों सीएचसी को शासन की ओर से पत्र भेजकर वहां मौजूदा संसाधनों की सूची मांगी गई है। यहां आक्सीजन की व्यवस्था होगी और कोरोना के इलाज के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। दो दर्जन जिलों में कोरोना के 100 से कम रोगी - प्रदेश में 24 जिलों में अब कोरोना के 100 से कम मरीज रह गए हैं। वहीं इसमें 10 जिले ऐसे हैं, जहां अब 50 से भी कम मरीज हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से घट रहा है। पिछले 24 घंटे में 2.84 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई तो उसमें से 797 लोग संक्रमित पाए गए। अब पाजिटिविटी रेट घटकर 0.2 प्रतिशत रह गया है। सक्रिय केस घटकर 14,067 - अब तक कुल 16.99 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 16.64 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट बढ़कर 97.9 फीसद हो गया है। मंगलवार को कोरोना से 94 और रोगियों की मौत हुई। अब तक कुल 21,425 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। अब सक्रिय केस घटकर 14,067 रह गए हैं। यूपी में जिन 10 जिलों में 50 से कम मरीज हैं, उनमें कौशांबी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, कासगंज, फतेहपुर, कन्नौज, बांदा और श्रावस्ती शामिल हैं।

गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, गेंद मायावती के पाले में

गाजियाबाद । जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाने की कोशिश में जुटी भाजपा की राह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनने के बाद और मुश्किल हो गई है। चौदह सदस्यीय जिला पंचायत में वर्तमान में भाजपा के पास दो जीते व एक समर्थित सहित मात्र तीन सदस्य हैं जबकि सपा- रालोद गठबंधन के छह सदस्य हो गए हैं। जीत के लिए जरूरी आठ सदस्यों में से सपा-रालोद गठबंधन को अब मात्र दो सदस्यों की जरूरत है जबकि भाजपा को पांच सदस्य चाहिए। भाजपाइयों को उम्मीद है कि पूर्व में गठबंधन का कड़वा अनुभव देख चुकी बसपा अंत में उसे समर्थन दे देगी वहीं बसपा से निष्कासित विधायक असलम चौधरी अपनी ही पार्टी में सेंध लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत त्यागी की पत्नी ममता त्यागी पर दाव खेला है, जबकि सपा- रालोद गठबंधन ने बसपा विधायक असलम चौधरी की पत्नी की नसीम बेगम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों दलों के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब बसपा के पांच सदस्यों पर ही अब चुनाव टिका है। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव बसपा और सपा ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन न तो चुनाव बाद परिणाम बेहतर आए और न ही कार्यकर्ताओं के मन मिले। अब सपा ने जिस प्रकार से बसपा के निष्कासित विधायक असलम चौधरी की पत्नी नसीम पर दाव खेला है इससे कहीं न कहीं बसपाई खेमा आहत है। भाजपा इसी का लाभ उठाने की जुगत में है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ममता त्यागी के पति बसंत त्यागी दावे के साथ कह रहे हैं कि चुनाव में बसपा के सभी पांच सदस्य उनके साथ रहेंगे। जबकि बसपा ने फिलहाल इस मामले पर अभी तक पूरी तरह से चुप्पी साध ली है।

कैप्टन सरकार पर बरसे अकाली; कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन पर स्वास्थ्य मंत्री, जीरकपुर कौंसिल अध्यक्ष केस दर्ज करने की मांग

मोहाली । शिरोमणि अकाली दल के वर्करों व पदाधिकारियों ने सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, जीरकपुर नगर परिषद के अध्यक्ष उदयबीर सिंह ढिल्लों, युवा कांग्रेसी नेता वरिंदर ढिल्लों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपइंद्र सिंह ढिल्लों, गुरप्रीत कांगड व कई नेताओं पर मामले दर्ज करने की मांग एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह से की है। डेराबस्सी से विधायक एनके शर्मा बुधवार को सुबूतों के साथ एसएसपी से मिले। शर्मा ने कहा कि अगर शिअद ने लोगों की आवाज उठाने के लिए रैली में कोविड नियम तोड़े तो कांग्रेसी हर रोज नियम तोड़ रहे हैं। नियम तोड़ने में सबसे आगे सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू हैं क्योंकि वे हर रोज गलियों व नालियों का नींवपत्थर रखने के लिए 200-200 लोग एकत्रित कर रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि आप पर मामला तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया गया है। अकालियों ने कहा कि अगर कांग्रेसियों पर मामले दर्ज न किए गए तो पंजाब भर में प्रदर्शन किया जाएगा। शिअद पदाधिकारियों को अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो वे तैयार है। विधायक एनके शर्मा ने सेहत मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने वैक्सीन, फतेह किट, वेंटीलेटर घोटाला किया है। इसे लेकर शिअद संघर्ष तब तक जारी रखेगी जब तक कि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती। शर्मा ने इस मामले में पंजाब की मुख्य सचिव पर भी आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि मुख्य सचिव ट्वीट कर लोगों को निजी अस्पतालों से टीका लगवाने की सलाह देती हैं। सेहत मंत्री पहले टीके की कमी बताते हैं और बाद में खुद ही 40 हजार डोज होने का दावा कर देते हैं। खुद ही चोरी करते है और खुद ही चोरी पकड़ लेते हैं। सेहत मंत्री की ओर से बुधवार को सरकारी कॉलेज का नींव पत्थर रखे जाने पर भी शर्मा ने सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि वर्ष 2015 में जीरकपुर को मेडिकल कॉलेज मिला था। इसके लिए 50 करोड़ रुपये मिले थे लेकिन सेहत मंत्री ने कॉलेज मोहाली शिफ्ट करवा लिया। पांच साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाए। आज दीवार पर अपने नाम का पत्थर लगाने पहुंच गए। शर्मा ने कहा कि सेहत मंत्री को सिर्फ नींवपत्थर रखने का शौक है।

ये बोले एसएसपी सतिंदर सिंह– एसएसपी मोहाली सतिंदर सिंह ने कहा कि विधायक एनके शर्मा आज शिकायत देकर गए है। सिंह ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन सबके लिए है। गाइडलाइन का सबको पालन करना चाहिए। जो शिकायत दी है उसकी जांच पर कार्रवाई होगी।

जेपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अब नई नियमावली के आधार पर होगी चार वर्षों की परीक्षा

रांची । झारखंड सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा अब संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (सातवीं) चार वर्षों वर्ष 2017, 2018, 2019 तथा 2020 तक के लिए एक साथ ली जा रही है। विभिन्न सेवाओं में कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल फरवरी-मार्च में ही आवेदन मंगा लिए गए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा दो मई को ही होनेवाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्य सरकार ने छठी सिविल सेवा परीक्षाओं में हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा के लिए भी कई बदलाव किए हैं। इसके लिए पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली गठित की गई। इसमें परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत 1,050 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी जिनमें साक्षात्कार के भी 100 अंक शामिल हैं। छह पत्रों की मुख्य परीक्षा में पहला पत्र मात्र अर्हक (क्वालिफाइंग) प्रकृति का होगा तथा इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। छठी सिविल सेवा परीक्षा में इसी विषय के अंकों को मेरिट सूची में जोड़ दिया गया था। अब संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अवसर की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। साथ ही इस परीक्षा में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म कर दी गई है। दरअसल, पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कट ऑफ मार्क्स के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना नहीं हो पाती थी, क्योंकि इन श्रेणियों के छात्रों को अंक कम आते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता हटने से अधिक से अधिक छात्र मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइ करेंगे, क्योंकि उसे उस सीमा तक घटाया जा सकेगा जिससे 15 गुना हो जाए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण-पोषण भत्ता की सौगात, खाते में भेजे 1-1 हजार रुपये

लखनऊ । कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में दिहाड़ी पर काम करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों संबल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1000 रुपये की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पांच श्रमिकों को खुद 1000 रुपये की राशि के चेक सौंपे। यह राशि देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद भी किया।

अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले सवा साल से कोरोना के खिलाफ लगातार जारी जंग में श्रमिकों ने हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसका मुकाबला किया है। पिछले साल संक्रमण की पहली लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की वजह से चुनौती ज्यादा थी। 40 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे जिनके भरण पोषण से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था सरकार ने की। दुनिया के तमाम संस्थान यूपी के इस सफल मॉडल पर शोध कर रहे हैं। श्रमिकों के हितों का ख्याल रखते हुए हम कोरोना की पहली लहर से पार पा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने और इनको हितों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने प्रदेश में आयोग गठित किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में बड़े और छोटे उद्योग चलते रहे, खेती बाड़ी का काम जारी रहा। हमने निर्माण कार्य भी बंद नहीं होने दिया। औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क का गठन कर हमने सभी श्रमिकों को सुरक्षित रखने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि सरकार प्रदेश के अंदर संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। यह काम शुरू हो गया है। इसी तरह हर श्रमिक का पंजीकरण कराकर उन्हें पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले गरीब मजदूरों का राशन कार्ड बनता नहीं था। सत्ताधारी दल से जुड़े परिवारों के ही राशन कार्ड बनते थे। हमने अभियान चलाकर सभी गरीब मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराया। अपने उद्बोधन में वह मजदूरों को आगाह करने से नहीं चूके कि कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतें और आवश्यक कदम उठाएं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्र भी मौजूद थे।

बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने आंशिक कर्फ्यू लगाया था। इसका फायदा भी देखने को मिला, क्योंकि प्रदेश में डेली नए केस के आंकड़ें तेजी से कम हो रहे हैं। हालांकि, इसका बुरा असर उन लोगों पर पड़ा है, जो दिहाड़ी पर काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मदद के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है ताकि दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों, पटरी और फेरी दुकानदारों को जीवन यापन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का फैसला किया है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान घोषित लॉकडाउन में पंजीकृत 20.37 लाख श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता मिला था।

बता दें कि कोरोना की विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार ने ठेला-खोमचा लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार एक माह के लिए 1000 रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का फैसला किया है। यह योजना फिलहाल एक माह के लिए लागू की गई है। श्रम विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य बीओसीडब्लू में वर्तमान में 98 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 67.37 लाख श्रमिकों का पंजीकरण नवीनीकृत है। इस लिहाज से वे भरण-पोषण भत्ता पाने के हकदार हैं।

समय से पहले पूर्वी यूपी में दस्तक दे सकता है मानसून, स्वागत के लिए हो जाएं तैयार

लखनऊ । गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून उत्तर प्रदेश में लगभग एक हफ्ते पहले ही दस्तक दे सकता है। बुधवार से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अगले तीन-चार दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की आमद हो सकती है। इसके साथ ही राजधानी में भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। बुधवार से प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और राजधानी के साथ-साथ पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बौछारें पड़ने व तेज हवा चलने की संभावना है।

मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक-दो दिन में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जिसके चलते मॉनसून सक्रिय होगा और अगले दो-तीन दिन में इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 1 हफ्ते पहले मॉनसून आने की आहट है। उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में यूपी में 18 जून के आसपास मानसून की आमद होती है लेकिन इस बार यह एक हफ्ते पहले ही दस्तक दे सकता है। मानसून की चाल सामान्य रही तो राजधानी में भी तिथि से पहले ही मानसून आ जाएगा । उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक-दो दिन में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है जिसके चलते मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। बुधवार से प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी जिसके चलते बदली तेज हवाएं अलग-अलग स्थानों पर बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

राजधानी में मंगलवार को कुछ स्थानों मेंबहुत सारी पड़ी। अमौसी वेदर स्टेशन पर3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि शहर के कई हिस्सों में दो-चार बूंदे ही पड़े अधिकतम तापमान सामान्य के करीब 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गयावहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है।

सीएम नीतीश से दोस्ती, बीजेपी से बैर; जानें क्या है जीतन राम मांझी की ट्विटर पॉलिटिक्स के मायने

पटना । लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्विटर पॉलिटिक्स खूब परवान चढ़ी। ट्विटर पर राजनीति और प्रेशर पॉलिटिक्स करने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खूब धमाल मचाया। अपने ट्वीट के जरिए वे एनडीए में शामिल होकर भी सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में बीजेपी पर जमकर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। चाहें एनडीए में भाजपा हो, पीएम नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष अपने ट्वीट की चहचहाहट से सबको निशाने पर लिया। हालांकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर वे बिहारी अंदाज में खूब तंज करते हैं, मगर उनके पिता और राजद अध्यक्ष लालू यादव को मैरिज एनीवर्सिरी की बधाई देते हैं। अपने बेबाक ट्वीट से वे सबको चौंकाते रहते हैं। सवाल यह है कि एनडीए में रहकर नीतीश से दोस्ती और बीजेपी से बैर में मांझी की कौन सी नई राजनीतिक चाल है।

अभी ताजा उदाहरण बिहार में दलित-मुस्लिम संघर्ष को लेकर सरकार पर हमलावर बीजेपी का है। बीजेपी का जवाब मांझी ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। बिहार के पूर्णिया, चंपारण, गोपालगंज और जमुई को लेकर बीजेपी के नेता दलितों पर कथित अत्याचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता व मंत्री जनक राम ने कहा था कि गोपालगंज और जमुई में महादलितों का मत परिवर्तन कराया जा रहा है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने पूर्णिया के एक गांव में अल्पसंख्यकों पर दलितों की बस्ती में आग लगाने का आरोप लगा स्थानीय प्रशासन की आलोचना की थी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने चंपारण की दलित-मुस्लिम घटना का जिक्र करते फेसबुक पोस्ट किया। इसके बाद मांझी का ट्वीट आया- पूर्णिया की घटना के बाद वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज के भाइयों के पक्ष में खड़े रहकर दिखा दिया कि सूबे के दलित-मुस्लिम एक जुट हैं। दलित मुस्लिम एकता से जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वहीं बिहार सरकार पर अंगुली उठा रहे हैं। मांझी ने हाल ही में पीएम मोदी को भी ट्वीट कर निशाने पर लिया था। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसपर संबंधित राय के सीएम की भी तस्वीर होनी चाहिए। दूसरी ट्वीट में कहा - यदि प्रधानमंत्री को अपनी तस्वीर छपवाने का इतना ही शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी छपवा लें। इसके बाद बिहार एनडीए में खूब हंगामा बरपा था। उसी दिन शाम में मांझी ने पीएम मोदी पर अपनी दूसरी ट्वीट डिलीट कर दी थी।

कभी योगी को भी मांझी ने खूब दी थी नसीहत– देखा जाए तो जीतन राम मांझी योगी आदित्यनाथ को कभी भी खास पसंद नहीं करते थे। एक बार तो योगी के बिहार दौरे के दौरान उन्होंने साफ कह दिया था कि दौरे पर बिहार आए हैं तो आए कोई किसी को कहीं जाने से रोक थोड़े सकता है। मगर यहां अपने सांप्रदायिकता का जहर नहीं फैलाए। मांझी यहीं नहीं रूके। आगे कहा कि वो यहां हनुमान जी की भी बातें भी ना करें। योगी हनुमान जी को भी जाति में बांट देते हैं। इसके अलावा वो बिहार में जाति-पाति और मंदिर-मस्जिद की राजनीति ना करें।

गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई, सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें व प्रतिष्ठान

शिवहर । कोरोना वायरस के मद्देनजर राय सरकार के निर्देश पर जिले में लाकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जिले में नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। पूर्व में जारी गाइडलाइन में कुछ संशोधन करते हुए रियायत दिया गया है। इसके तहत बाजार और दुकान खुलने का समय सुबह छह से शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। हालांकि, इस अवधि में सभी दुकानें सप्ताह में केवल चार दिन ही खुलेगी। इसके लिए डीएम सजन राजशेखर ने बुधवार, शुक्रवार रविवार और मंगलवार का दिन तय किया हैं। पूर्व में दोपहर दो बजे तक ही दुकान खोलने का समय तय किया गया था।

हालांकि, खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि उपकरण, जरूरी खाद्य सामग्री, दवा, दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह छह बजे से शाम दो पांच बजे तक खुली रहेगी। 15 जून तक जिले के तमाम निजी क्षेत्र के कार्यालय, माल, जिम, पार्क, उद्यान, क्लब, सिनेमाघर, मंदिर-मस्जिद समेत धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल, कालेज व कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। 50 फीसद कर्मी के साथ सरकारी कार्यालयों में कामकाज जारी रहेगा। हालांकि, निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह और श्राद्धकर्म में पूर्व का आदेश जारी रहेगा। शादी समारोह और श्राद्धकर्म में 20 लोग ही भाग ले सकेंगे। बारात निकालने और बैंड बजाने पर भी रोक रहेगी। डीजे का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। सरकारी कार्यालय, दुकान और बाजार में दो गज की दूरी, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। जबकि, सार्वजनिक वाहन का परिचालन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 फीसद यात्री के साथ जारी रहेगा। शहरी क्षेत्र में भीड़ पर नियंत्रण की जिम्मेदारी एसडीओ की होगी। जबकि, प्रखंडों में इसकी जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को दी गई है।

डीएम सजन राजशेखर ने अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बीडीओ-सीओ और इओ को आम जनता को जागरूक करने के लिए माइकिंग कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने नए गाइडलाइन का पालन कराने के जिले के सभी अधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही आम जनता से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने, मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का पालन करने तथा टीकाकरण कराने की अपील की है।

प्रतिबंध की श्रेणी से रखा गया हैं बाहर– बैंक, बीमा, एटीएम व गैर वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक और विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कामर्स, कुरीयर सेवा, कृषि और इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया, संचार, इंटरनेट, ब्राडकास्टिंग और केबल सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी से जुड़ी सेवा और भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेले पर घूमघूम कर फल और सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अस्पताल, निजी अस्पताल, मानव व पशु स्वास्थ्य सेवा आधारित दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान, दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम आदि का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। जबकि, होटल-रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सेवा सुबह नौ से रात नौ बजे तक जारी रहेगा। होटलों में आंगतुकों को इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा।

गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान होगी सील – नई गाइडलाइन के तहत दुकानदार, स्टाफ और ग्राहक समेत सभी को मास्क लगाकर रहना होगा। दुकान-प्रतिष्ठानों में हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी। दुकान-प्रतिष्ठानों में दो गज की दूरी का पालन कराना दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। इसके लिए दुकान के आगे गोल घेरा बनाना होगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुकानें सील कर दी जाएगी। डीएम द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार के वाहन के परिचालन समेत पैदल चलने पर भी रोक रहेगी।

उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बताया यशस्वी मुख्यमंत्री, मदद की लगाई गुहार

पटना । बिहार की राजनीति में आजकल एक से बढ़कर एक आश्चर्य हो रहे हैं। बिहार में भाजपा , जदयू, राजद , हम और कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ है और किसके विरोध में। जदयू में अपनी वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा कई ऐसे बयान दे चुके हैं, जिनसे बिहार में सहयोगी दल भाजपा के नेता असहज हुए हैं। आज फिर उनके एक बयान से बीजेपी चौंक सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड के ष्ट्रू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को यशस्वी मुख्यमंत्री कहा है। उन्होंने झारखंड के सीएम से मदद की गुहार भी लगाई है।

हेमंत ने बिरसा मुंडा की जयंती पर यह बयान दिया है। उन्होंने झारखंड के सीएम को यशस्वी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा है कि आज पूरा राष्ट्र बिरसा मुंडा को भारत रत्न देने की मांग करते हुए उनकी शहादत को याद कर रहा है। ऐसे समय में भगवान बिरसा की पड़पोती के सड़क के फुटपाथ पर बैठ कर सब्जी बेचने की खबर अछी नहीं लगती। यह समाचार मन को विचलित कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने हेमंत से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा साफ-सुथरी छवि और बेलाग बात रखने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि वे हेमंत को यशस्वी मुख्यमंत्री कहने के पीछे सामान्य शिष्टाचार की बात कहें। लेकिन बिहार की राजनीति में आज कल इतनी तल्खी है ।

यूपी में अब 12 हजार कोरोना के एक्टिव केस, 24 घंटों में मिले 700 नए पॉजिटिव

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने बुधवार से दिन का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू (शनिवार और रविवार) जारी रहेगा। बीते चौबीस घंटों के दौरान 2.90 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई जिसमें 700 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब राज्य में कुल कोरोना के सक्रिय मामले 12 हजार रह गए हैं। अब राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.2 फीसद और रिकवरी रेट 98 फीसद है।

उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सफल सिद्ध हुई है। इसी का परिणाम है कि लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने कुल सक्रिय केस हैं उससे अधिक कई राज्यों में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या आ रही है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश से आधी है, लेकिन वहां कोरोना केस प्रतिदिन कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 10 प्रतिशत भी नहीं है फिर भी वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार महाराष्ट समेत कई राज्यों ने संपूर्ण लाकडाउन लगाया जिससे आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं। इससे प्रतिदिन काम कर कमाने वालों के समक्ष जीविका का संकट आ गया। उद्यम और बाजार बंद होने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, जबकि यूपी में केवल कोरोना कर्फ्यू रहा जिससे आर्थिक गतिविधियां थमीं नहीं। सावधानी के सभी उद्यम चलते रहे, आवश्यक वस्तुओं के बाजार खुले रहे। सभी उद्यम इकाइयों की कोविड हेल्प डेस्क और कोविड केयर सेंटर के साथ आर्थिक गतिविधियां जारी रखने में सफलता प्राप्त की गई।

यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके - यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 4.57 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने को अब केंद्रों पर भीड़ जुट रही है। अभी तक उप्र में कुल 2.11 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 1.76 करोड़ ने पहली व 36.78 लाख ने दूसरी डोज लगवाई है। फिलहाल प्रदेश में जून में एक करोड़ और जुलाई में तीन करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।आंकड़ों के मुताबिक बीती सात जून यानी सोमवार को यूपी में सबसे ज्यादा टीके लगाए गए।

एक दिन में यदि दूसरे राज्यों में लगाए गए टीके से तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश में 3.86 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और यहां अब तक कुल 1.32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में 2.93 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और अब तक कुल 2.47 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 66 हजार ने वैक्सीन लगवाई और अब तक कुल 57.86 लाख लोगों ने टीका लगवाया है। उधर बिहार में 93 हजार लोगों द्वारा एक दिन में टीका लगवाए जाने के बाद अब तक कुल 1.12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

यूपी में एक संक्रमित व्यक्ति के मुकाबले सर्वाधिक 30 लोगों की जांच - यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के मुकाबले 30.5 लोगों की जांच की गई। एक संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने के लिए इतने ज्यादा टेस्ट दूसरे किसी राज्य में नहीं किए गए। दूसरे नंबर पर दिल्ली में प्रति संक्रमित व्यक्ति 14 लोगों का और तमिलनाडु में 12.8 लोगों का टेस्ट किया गया। देश में सर्वाधिक 5.19 करोड़ लोगों की जांच यूपी में हुई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 16.99 लाख लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें 16.64 लाख ठीक हो चुके हैं।

अब तक 5.19 करोड़ लोगों की कोरोना जांच हुई है। ऐसे में एक संक्रमित की पहचान करने में यहां 30.5 लोगों के टेस्ट किए गए। इसी तरह दिल्ली में 14.29 लाख लोग संक्रमित हुए और दो करोड़ लोगों की जांच की गई है। यहां प्रति संक्रमित व्यक्ति 14 लोगों की जांच की गई। वहीं तमिलनाडु में 22.74 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और वहां 2.90 करोड़ लोगों की जांच की गई। तमिलनाडु में यह अनुपात 12.8 प्रतिशत है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 11.4, कर्नाटक में 11.5, केरल में आठ व महाराष्ट्र में एक संक्रमित व्यक्ति के मुकाबले 6.4 लोगों की जांच की गई है। फिलहाल यूपी में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फार्मूला पूरे देश में हिट साबित हो रहा है।

नागांव जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोग अपने कोविड-19 परीक्षण की प्रतीक्षा करते हुए ।

एनएचएम का एक कार्यकर्ता जम्मू के बाहरी इलाके में एक धान के खेत में कोविड-19 परीक्षण के लिए एक मजदूर का स्वाब नमूना एकत्र करते हुए ।

मुंबई के हिंदमाता में एक जलमग्न सड़क से गुजरने की कोशिश करते हुए एक टैक्सी चालक अपनी कार को धक्का देते हुए ।

एक नजर

लिक्विड नैनो यूरिया बदलेगा किसानों की किस्मत, गुजरात से 15000 बोतल मंगवाया

श्रीनगर । जम्मू कश्मीर के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। पहली बार स्थानीय किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने का अवसर मिलने जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप से गुजरात से 15000 बोतल लिक्विड नैनो यूरिया मंगवाया गया है, जो परंरागत यूरिया के 675 मीट्रिक टन के बराबर है। उपराज्यपाल ने इफको (इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड) को जम्मू कश्मीर में लिक्विड नैनो यूरिया उत्पादन का एक बड़ा सयंत्र स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार सभी प्रकार से मदद करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को वर्चुल मोड पर कलोल, गुजरात स्थित इफको के नैनो यूरिया सयंत्र से जम्मू कश्मीर के लिए लिक्विड यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में कृषि क्रांति का असर चारों तरफ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि 30 हजार किसानों को 65 करोड़ रुपये मूल्य के अत्याधुनिक कृषि उपकरण और 91 करोड़ की लागत से 25 हजार किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने इफको के प्रबंध निदेशक डा. यूएस अवस्थी व उनके साथियों को विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया विकसित तैयार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ फसलों का उत्पादन बल्कि मौसम के कारण फसलों का होने वाली क्षति पर भी काबू पाया गया है। 15000 बोतल नैनो यूरिया 675 मीट्रक टन यूरिया के बराबर = कलोल, गुजरात से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई लिक्विड नैनो यूरिया की 15000 बोतल 675 मीट्रिक टन परंपरागत यूरिया के बराबर है। जम्मू और कश्मीर संभाग के किसानों में बराबरी के आधार पर 7500-7500 बोतल लिक्विड नैनो यूरिया बांटा जाएगा।

सस्ता है नैनो यूरिया = उपराज्यपाल ने कहा कि नैनो यूरिया के इस्तमाल से कृषि लागत घटेगी। इससे सब्सिडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सरकार इस तरह 27 हजार करोड़ रुपये बचाएगी और किसानों को भी 28 हजार करोड़ का लाभ पहुंचाएगी। बासमती की कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी = उपराज्यपाल ने कहा कि 60 हजार हेक्टरेय में फैली बासमती की कृषि भूमि को और अधिक उत्पादक बनाया जाएगा। जारी वित्त वर्ष के दौरान हमने 7.5 लाख किसानों को 16 करोड़ की लागत पर बढिय़ा बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस पूरे अभियान के दौरान किसानों को जैविक कृषि अपनाने लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नैफेड करेगा 1700 करोड़ रुपये का निवेश = जम्मू कश्मीर के बागवानी क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने बताया कि नैफेड के साथ एक एमओयू तय किया गया है। इसके तहत अगले पांच साल के दौरान सेब, अखरोट, आगम और लीची के उच्च पैदावार वाले पेड़ों के बाग 5500 हेक्टयर में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जम्मू कश्मीर में 1700 करोड़ का निवेश नैफेड करेगा। इसके अलावा 500 करोड़ के निवेश से कठुआ और उत्तरी व दक्षिण कश्मीर में तीन कोल्ड स्टोर भी बनाए जाएंगे।

स्कूलों के पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी की तर्ज पर अपडेट 31 अगस्त तक करें

जम्मू । जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि एनसीईआरटी की तर्ज पर स्कूलों का पाठ्यक्रम 31 अगस्त तक अपडेट किया जाए। यह शिक्षा नीति का हिस्सा है। शिक्षा में गुणवत्ता लाए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने उन्होंने कहा कि ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मिड डे मील योजना की स्टेरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सरकारी स्कूलों में पंजीकरण और ड्रॉपआउट दर पर की समीक्षा भी की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि वे ड्रॉपआउट के कारणों का पता लगाएं और इससे काम करने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने लिंग अनुपात समानता सुनिश्चित बनाने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अध्यापकों के मुकाबले बच्चों के पढ़ाने की दर का समायोजन किया जाए। विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए हर स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक जरूरत अनुसार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की तर्ज पर 31 अगस्त तक अपडेट किया जाए। विभाग से कहा कि अध्यापकों के प्रदर्शन पर मापदंड एक महीने के अंदर तैयार होने चाहिए और पारदर्शिता लाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर नीति में शिफ्ट होना चाहिए। उन्होंने मिड डे मील योजना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की और इसके लिए खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ तालमेल कायम करने पर जोर दिया। बैठक में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर के निदेशक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मादक पदार्थ का गढ़ रहा जम्मू, रोजाना पकड़े जा रहे तस्कर, रोकने के लिए हाईवे पर बढ़ेंगे नाके

जम्मू । कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी में काफी हद तक अंकुश लगा था, लेकिन अब अन-लॉक शुरू होते ही तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बीते मंगलवार को जम्मू पुलिस ने विभिन्न हिस्सों से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त चार लोगों को दबोचने का दावा किया था। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने हेरोइन, चरस, कोकीन और भुक्की को बरामद किया था। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए लोगों ने यह खुलासा किया है कि मादक पदार्थों को उन्होंने कश्मीर से हासिल किया है। जिसके चलते पुलिस ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बीते मंगलवार को दोमाना पुलिस ने एक युवक को 11.19 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा था।

कोकीन अकसर जम्मू में कम ही पाई जाती है। इसके अलावा कानाचक्क पुलिस ने एक युवक को 105 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसी तरह मंगलवार को ही सिदड़ा पुलिस ने एक युवक साहिल अली को चार ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पुलिस सख्त- एसएसपी जम्मू चंदन कोहली का कहना है कि जम्मू पुलिस ने नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी करने के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान में उन्हें लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी दे रहे है। उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक व्यायाम और खेलों में समय व्यतीत करने की सलाह दी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ेंगे नाके- पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू में नशे की खेप अकसर कश्मीर से लाई जाती है। ऐसे में करीब तीन सौ किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग में नाकों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत कर रहा है।

इंटेलिजेंस सूचना, अशोक गहलोत कैंप के कुछ विधायक सचिन पायलट के संपर्क में

जयपुर । राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने पार्टी आलाकमान को अल्टीमेटम दिया है कि या तो जुलाई तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने का वादा पूरा करो, नहीं तो वे आगे निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। पिछले दो दिन में एक दर्जन विधायकों ने पायलट के घर अलग-अलग बैठक कर एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति बनाई। पायलट खेमा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से अगले माह मुलाकात का समय मांगेगा। विधायकों के साथ ही जिला प्रमुख, प्रधान,स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और जिला स्तर के कांग्रेसियों से भी पायलट की बात होने की जानकारी है। दो दिन बाद स्व.राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हर साल की तरह शुक्रवार को होने वाली प्रार्थना सभा में अपनी ताकत दिखाने की रणनीति भी पायलट कैंप ने बनाई है।

उधर इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के बाद सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और गुजरात से सटे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। कभी भी बॉर्डर सील हो सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को इनपुट दिया कि पायलट समर्थक विधायक दिल्ली अथवा पड़ौसी राज्यों में जाकर एक बार फिर बाड़ेबंदी कर सकते हैं। विधायकों के साथ स्थानीय निकाय व पंचायत प्रतिनिधियों के भी जाने की सूचना है । इंटेलिजेंस सूचना है कि इस बार गहलोत कैंप के कुछ विधायक भी पायलट के संपर्क में है । मौका मिलते ही वे ही पाला बदल सकते हैं ।

दोनों खेमे सक्रिय हुए,आलाकमान की नजर

बुधवार सुबह से ही गहलोत और पायलट खेमे सक्रिय हो गए। गहलोत के विश्वस्त संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया,राज्यमंत्री सुभाष गर्ग, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अपने कैंप के विधायकों को फोन कर उनका मन टटोला। कुछ से व्यक्तिगत मुलाकात भी की। साथ ही पायलट समर्थक विधायकों से भी बात की। उधर पायलट के विश्वस्त विधायक रमेश मीणा,मुरारी मीणा व वेदप्रकाश सोलंकी ने अपने खेमे के विधायकों को एकजुट करने की तैयारी शुरू की है। ये विधायक निर्दलीयों के साथ ही बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों से भी संपर्क साध रहे हैं।

पंजाब पर ध्यान, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं पायलट खेमे ने कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी.वेणुगोपाल,प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बात कर कह कि जब पंजाब के विवाद को लेकर आलाकमान इतनी सक्रियता देखा सकता है तो राजस्थान के मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। पंजाब के नेताओं से आलाकमान की कमेटी ने बात भी कर ली। लेकिन राजस्थान को लेकर बनाई गई समिति की एक भी अधिकारिक बैठक नहीं हुई ।

मुद्दों का समाधान नहीं होने पर जताई नाराजगी- एक बातचीत में सोलंकी ने कहा कि जहां अनुसूचित जाति,जनजाति और अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलते वहां कांग्रेस के नेता चुनाव लड़कर देख ले कि क्या चुनाव परिणाम रहता है । वहां हार होगी । उन्होंने कहा,वोट हमारे और मलाई दूसरे खा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। सोलंकी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि 10 माह से केबिनेट में एक भी दलित केबिनेट मंत्री नहीं है,हम जैसे दलित विधायक केस के सामने दुखड़ा रोएं । सोलंकी ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जिन लोगों ने लाठियां खाई,तत्कालीन भाजपा सरकार में आंदोलन किए वे आज परेशान है और पांच साल तक एयरकंडिशन में बैठने वाले सत्ता का मजा ले रहे हैं । कार्यकर्ता देखते रह गए और सेवानिवृत अधिकारियों को नियुक्तियां दी जा रही है ।

दलितों के खिलाफ फैसलों में सीएम के खास मंत्री का हाथ- राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीतकर गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सुभाष गर्ग पर निशाना साधते हुए सोलंकी ने कहा कि दलितों के खिलाफ फैसलों में उन्ही का हाथ है । गर्ग ने ही मुख्यमंत्री से गलत फैसले करवाए हैं। वे गहलोत के खास हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या गर्ग ही पूरे राजस्थान की राजनीति समझते हैं ।

सोलंकी ने कहा कि दलित समाज से भरोसी लाल जाटव और टीकाराम जुली को राज्यमंत्री बना रखा है । लेकिन उन्हे नाम मात्र के विभागों में केबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में लगा रखा है । ये दोनों एक या दो मंत्रिमंडलीय कमेटी में हैं, जबकि गर्ग 9 को 9 कमेटियों में शामिल किया गया है। सोलंकी ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर सत्ता व संगठन में हो रहे फैसलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई । जानकारी के अनुसार पायलट खेमे के विधायकों ने मंगलवार को अनौपचारिक रूप से बैठक कर आगे की रणनीति तय की ।

गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 695 के सामने है जबकि 11 लोगों की मौत

अहमदाबाद । गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 695 मरीज सामने आये हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 14, 724 है जबकि अब तक 79, 3028 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,58, 797 लोगों को टीका लगाया गया राज्य में अब तक 18914643 टीके लगाए जा चुके हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका में 108 केस दर्ज किए गए जबकि मरने वालों की संख्या 3 रही है। वडोदरा में 99 केस मिले है, एक की मौत हो गई है , सूरत में 79 केस मिले हैं, एक की मौत, राजकोट में 32 केस मिले है, जामनगर में 18 केस मिले है, एक की मौत, जूनागढ़ में 11 केस मिले है, मौत का आंकड़ा शून्य है, वहीं गांधीनगर में भी कोरोना संक्रमण के आठ केस सामने आए है, जबकि मौत का आंकड़ा शून्य रहा है। विविध जिलों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस प्रकार रहे- सूरत में कोरोना संक्रमण के 30 केस दर्ज किया गए। वडोदरा में 41 केस दर्ज किए गए हैं। राजकोट में 19 केस मिले हैं, , मेहसाणा में 19 केस मिले हैं, , अहमदाबाद में 5 मिले जबकि गांधीनगर में संक्रमण के 4 केस दर्ज किए गए हैं ।

कोविड के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी सिंजेंटा

कोलकाता । अपने कोविड सहायता कार्यक्रम के तहत देश की प्रमुख कृषि कंपनी सिंजेंटा इंडिया ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान संस्थागत ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया है। कोविड की दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों को अत्यधिक प्रभावित किया है। अपने चल रहे सीएसआर कार्यक्रम के जरिये सिंजेंटा इंडिया ने 15 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को 2,000 मेडिकल बेड वितरित किए हैं। अस्पताल में बिस्तरों की भारी कमी को देखते हुए कंपनी ने यह कदम उठाया।

इसके साथ ही कंपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स, ग्रामीण अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराकर भी लगातार मदद कर रही है।चादरों और तकियों के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल बेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण और अस्थायी अस्पतालों को देशभर में परीक्षण में तेजी लाने के लिए हजारों रैपिड टेस्ट किट भी प्रदान किए गए हैं।

इस पहल के बारे में बात करते हुए सिंजेंटा इंडिया के प्रबंध निदेशक, राफेल डेल रियो ने कहा, ÷हम इस कठिन समय में किसानों और ग्रामीणों का समर्थन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कोविड के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण अस्पताल में बेड की भारी कमी को देखते हुए, हमने तत्काल पूरे भारत में ग्रामीण अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,000 बेड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। मेडिकल बेड, मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट और सैनिटाइजर जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा हम चिकित्सा सामग्री व उपकरण निशुल्क मुहैया करा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसंटेटर, बेड, टेस्टिंग किट आदि।

सिंजेंटा इंडिया इन विपरीत परिस्थिति के दौरान किसानों की मदद करने के लिए उन तक महत्वपूर्ण जानकारी और परामर्श भी लगातार पहुंचा रही है।कंपनी ने किसानों की सहायता के लिए एक विशेष किसान कॉल सेंटर स्थापित किया है। कॉल सेंटर नौ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रदान कर रहा है। कॉल सेंटर के जरिये किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को जरूरी जानकारी मुहैया कराने के साथ कोविड सहायता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कॉउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। हेल्पलाइन नंबर 1800-1-215-315 है।

सिंजेंटा इंडिया के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर डॉ. केसी रवि ने कहा, ÷ये मेडिकल बेड ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में अधिक रोगियों को चिकित्सा मुहैया करने में मदद करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के मामलों की संख्या में अचानक आयी वृद्धि से जो बोझ बढ़ा है, वह कम होगा। हमारा ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करना है, ताकि वे लोगों की चिकित्सा आवश्यकता को पूरा कर सकें।

वर्ष 2020 में, कोविड -19 महामारी की पहली लहर के दौरान ही सिंजेंटा ने राष्ट्रीय स्तर पर कोविड सहायता कार्यक्रम शुरू किया। सिंजेंटा के इन कार्यक्रमों से 1.5 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हुए। पहली लहर के दौरान सिंजेंटा ने एक अनूठी पहल करते हुए लॉकडाउन के बीच किसानों को बाजार से जुड़ाव प्रदान कराया था। इस पहल ने किसानों को अपनी उपज का 2,442 मीट्रिक टन बेचने में मदद की, जिससे उन्हें 4.87 करोड़ रुपये की कमाई करने में मदद मिली।

बीएसएफ ने रात के अंधेरे में अवैध तरीके से सीमा पार जाने की कोशिश करते बच्चे समेत छह बांग्लादेशियों को पकड़ा

कोलकाता । बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने एक विशेष अभियान में रात के अंधेरे में अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघ कर उस पार जाने की कोशिश करते एक बच्चे समेत छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से एक बयान में बताया गया कि इन सभी को सात जून, मध्यरात्रि को बल की सीमा चौकी जीतपुर इलाके से 99वीं वाहिनी के जवानों ने पकड़ा।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति बांग्लादेश के बारिशाल और बगैरहाट जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान हसीना बेगम (40), साहिल शेख (18) आयशा शेख (22), मोहम्मद सिकंदर (28) एवं जिसके साथ 14 महीने का पुत्र है, सोहिल खान (27) के रूप में हुई। ये सभी उत्तर प्रदेश और कोलकाता में काम कर रहे थे। बयान में कहा गया कि सीमा चौकी जीतपुर की सीमा पर तैनात जवानों ने रात तकरीबन 11.30 बजे छह से सात संदिग्ध लोगों को भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर आते देखा। सुरक्षा में तैनात जवानों ने जब उन्हें रुकने को कहा, तो वो भागने लगे, लेकिन जवानों ने उनका पीछा कर गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ करने के लिए सीमा चौकी जीतपुर लेकर आए।

15 साल पहले गैर कानूनी रूप से भारत आए थे घुसपैठिए- पूछताछ के दौरान हसीना बेगम ने बताया कि वह 15 साल पहले गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी और उत्तर प्रदेश में बाई का काम करती थी। आयशा शेख और साहिल शेख दोनों उसके बेटी और बेटा हैं, और मोहमद सिकंदर उसका दामाद है। मोहमद सिकंदर ने बताया की वह 12 साल पहले भारत आया था और वह भी उत्तर प्रदेश में कबाड़ी का काम करता था। उसने बताया कि उसने आयशा शेख से शादी की और उनका एक बेटा है। वहीं, सोहिल खान ने बताया कि वह पांच महीने पहले गैर कानूनी तरीके से भारत आया था और कोलकाता के मल्लिक बाजार में कबाड़ी का काम करता था।

ये सभी लोग एक अनजान भारतीय दलाल की मदद से अब वापस बांग्लादेश जा रहे थे।इन लोगों ने बताया कि सीमा पार कराने के लिए उन्होंने दलाल को 26,000 रुपये दिए थे। हालांकि दलाल भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस थाना बगदाह को सौंप दिया गया है। इधर, 99वीं वाहिनी के कमांडिंग ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल कड़े कदम उठा रही है, जिसके चलते घुसपैठियों और दलालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कई पकड़े जा रहे हैं तथा उन्हें कानून के मुताबिक सजाएं भी हो रही हैं।

निम्न दबाव के पहले ही कोलकाता समेत विभिन्न जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू

कोलकाता । बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने जा रहे निम्न दबाव का अभी से असर दिखना शुरू हो गया है। कोलकाता समेत सूबे के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग में 11 से 14 जून तक दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कोलकाता, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हुगली समेत विभिन्न जिलों में बुधवार सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा है। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई।

जिलों में तापमान कई डिग्री उतर आया है पिछले कुछ दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। अलीपुर मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री पर सामान्य से एक डिग्री नीचे रहा। कोलकाता में पिछले 24 घंटे के दौरान 1.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।

कोलकाता में बुधवार को अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दक्षिण बंगाल में अभी कम बारिश होने पर भी उत्तर बंगाल में झमाझम बारिश हो रही है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंपोंग जैसे जिले बारिश से सराबोर हो रहे हैं।आने वाले दिनों में वहां बारिश और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 से दक्षिण बंगाल में होने वाली बारिश के साथ ही मानसूनी हवाएं भी सूबे के इस हिस्से में दस्तक दे देगी। मौसम विभाग में 11 से 14 जून तक दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है, मौसम विज्ञानी इस बार मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जता रहे हैं।

बागवानों के लिए प्रेरणास्रोत बने दुरगेला के पूर्ण चंद, सेबों की बाग़वानी कर बनाई पहचान

धर्मशाला । एक समय शाहपुर अपने अचारी आमों की बाग़वानी के लिए जगत् प्रसिद्ध था। शाहपुर के आमों की इस ख़ासयित को लोकगीतों में बयां किया गया। अब शाहपुर आमों की बाग़वानी के साथ सेबों की बाग़वानी में हाथ आजमाते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है।

शाहपुर तहसील के गांव दुरगेला के बाग़वान पूर्ण चंद ने प्रतिकूल भुगोलिक परिस्थितियों के बावजूद तीन सालों के भीतर सेबों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया कि अब वे आस-पास के बाग़वानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अब क्षेत्र में जब भी सेब की उम्दा पैदावार का ज़िक्र होता है तो पूर्ण चंद का नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। पूर्ण चंद ने वर्ष 2018 में प्रदेश के बाग़वानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेब का बगीचा लगाया था। उनकी कड़ी मेहनत से दो वर्ष के भीतर पौधों में फल आने शुरू हो गए। उन्होंने गत वर्ष लगभग छङ किवंटल सेब बेचा। उनके बाग़ीचे की विशेषता है कि वह अपने बाग़ीचे में किसी रासायनिक खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करते। इसके स्थान पर वह विभिन्न तरह से बनाये जानी वाली जैविक खादें, जोकि दालों, किचन वेस्ट, ऑयल सीड, गौमूत्र तथा गोबर द्वारा बनाई जाती हैं, का ही प्रयोग करते हैं। वह यह सब खुद ही तैयार करते हैं ।

बोले पूर्ण चंद अढ़ाई हजार पौधे बेचे- पूर्ण चन्द कहते हैं कि इस बार सेब की फ़सल काफ़ी अच्छी थी। लेकिन पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि तथा तूफ़ान से उन्हें नुक़सान पहुँचा है। लेकिन इसके बावजूद वह अब तक लगभग एक क्विंटल सेब बेच चुके हैं। सेबों की गुणवत्ता के चलते ख़रीददार उनके घर पर आकर ही सेब ख़रीद ले जाते हैं। उन्होंने ज़मीन लीज़ पर लेकर सेब के लगभग 25 हज़ार पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है। उनके पौधे गुजरात और महाराष्ट्र तक अपनी पहचान बना चुके हैं। पूर्ण बताते हैं कि इस वर्ष सर्दियों के मौसम में उन्होंने लगभग दो से ढाई हजार पौधे बेचे। इस दौरान क़रीब 25 परिवारों ने लगभग 50-50 पौधे लगाए हैं। वह सेब के पौधे लगाने में खुद लोगों की मदद करते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधे सर्दियों के मौसम में लगाए जाते हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा पौधों पर सब्सिडी के अलावा एन्टी हेलनेट के लिए भी पूर्ण चंद को 80 प्रतिशत उपदान दिया गया है। इस समय उन्होंने 3-4 कनाल के बाग़ीचे में लगभग 150 अन्ना तथा डोरसेट प्रजाति के पौधे लगाए हैं। उन्होंने बाग़ीचे की सिंचाई हेतु एक जल भंडारण टैंक बनाया है। वह पौधों की सिंचाई आधुनिक तकनीक से बनाई वाटर गन से करते हैं, जिससे कम समय और जल से पूरे बाग़ीचे की सिंचाई हो जाती है। उन्होंने अपने बग़ीचे में ओलावृष्टि तथा पक्षियों से बचाव हेतु एंटी हेलनेट भी लगाई है। पूर्ण चंद युवाओं से स्वरोज़गारी होने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वह अपनी ज़मीन को बंजर न छोड़ें और पारंपरिक खेती से हटकर बाग़वानी को अपनाकर सेब, कीवी और अमरूद आदि के पौधे लगाकर बाग़वानी शुरू करें। वह सेब के बग़ीचे लगाने में लोगों को पूर्ण सहयोग देते हैं। युवा प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सकते हैं।

एनडीए

सेना में अधिकारी बनने का अवसर

सेना में नौकरी करने का एक अलग ही क्रेज होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि देश सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। अब सैलरी भी काफी दमदार हो गई है। यही कारण है है कि अधिकतर युवा इस नौकरी को पाने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करता है।

अगर आप भी सेना में नौकरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम उम्र में ऑफिसर का रुतबा भी मिले, तो आपके लिए एनडीए बेहतरीन करियर विकल्प है। सेना में नौकरी करने का एक अलग ही क्रेज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको देश की सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। अब सैलरी भी अच्छी हो गई है। यही कारण है कि अधिकतर युवा इस नौकरी को पाने के लिए एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं।

एनडीए की परीक्षा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से काफी अलग होता है। अन्य परीक्षाओं में जहां मानसिक मजबूती देखी जाती है, तो वहीं इस परीक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों की मजबूती आवश्यक है। यही कारण है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले स्टूडेंट्स कम उम्र में ही सैन्य अधिकारी बन जाते हैं। अगर आप में भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है और ऑफिसर बनकर देश की बेहतर सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। एनडीए की ताजा परीक्षा के लिए केवल वही अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र साढे सोलह से उन्नीस वर्ष के बीच हो। सेना के तीनों अंगों के लिए पूर्णतया स्वस्थ अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 157.5 सेंटीमीटर (एयरफोर्स के लिए 162.3 सेंटीमीटर) और इसी अनुपात में वजन होना चाहिए।

इसके अलावा, एयरफोर्स एवं नेवी के लिए फिजिक्स व मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि, आर्मी विंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से बारहवीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। जो युवा बारहवीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के समय 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पेश करना होगा।

कुल 900 अंकों की परीक्षा

एनडीए परीक्षा में दो विषयों की कुल 900 अंकों की परीक्षा होती है-पहला, मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों के ढाई-ढाई घंटे के पेपर होंगे। मैथमेटिक्स का पेपर 300 और जनरल एबिलिटी का पेपर 600 अंक का होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और गलत उत्तरों के लिए अंक काटे जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए प्लानिंग बनानी होगी और उसी के अनुरूप तैयारी करनी होगी।

मानसिक मजबूती जरूरी

अन्य परीक्षाओं में जहां मानसिक मजबूती देखी जाती है, तो वहीं इस परीक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों की मजबूती आवश्यक है। यही कारण है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले स्टूडेंट्स कम उम्र में ही सैन्य अधिकारी बन जाते हैं। अगर आपमें भी ऑफिसर्स जैसी क्वालिटी है और ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है।

कठिन परीक्षा के लिए रहें तैयार

रिटेन टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को सेना के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी द्वारा इंटरव्यू और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कॉल किया जाता है। परीक्षा के इस चरण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की पर्सनैलिटी, उसकी बुद्धिमत्ता और सेना में एक ऑफिसर के रूप में उसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी (ओएलक्यू) को जांचना-परखना होता है। एसएसबी के सेंटर देश के कई शहरों में स्थित हैं और अभ्यर्थी को उसके निकटवर्ती सेंटर पर ही बुलाया जाता है। आमतौर पर एसएसबी इंटरव्यू पांच दिनों का होता है, लेकिन इसमें पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है।

स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया जाता है। शेष को अगले चार दिन तक कई टेस्ट देने होते हैं। इस दौरान उनका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू बोर्ड तथा ग्रुप टास्क ऑफिसर द्वारा अलग-अलग तरीके से आकलन किया जाता है और उनकी ओएलक्यू को जांचा-परखा जाता है। एनडीए परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी, खडगवासला, पुणे में तीन वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है।

खास बात यह है कि इस तीन वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान वे अपनी स्ट्रीम के अनुसार ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। इसके लिए उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एवं कंप्यूटर साइंस विषयों के साथ बीएससी का या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आदि विषयों के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए का विकल्प होता है। हालांकि ट्रेनिंग के पहले वर्ष में तीनों सेनाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक ही कोर्स की पढ़ाई करनी होती है।

दूसरे साल में उनके द्वारा चुने गए विंग यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के आधार पर उनके कोर्स का सिलेबस बदल जाता है। एनडीए में तीन वर्ष की ट्रेनिंग के उपरान्त कैडेट्स को उनके द्वारा चुनी गई विंग की विशेष जानकारी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। इसके तहत आर्मी के लिए चयनित कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी (देहरादून), एयरफोर्स के कैंडिडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी (हाकिमपेट) तथा नेवी के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को नेवल एकेडमी (लोनावाला) भेजा जाता है।

ट्रेनिंग के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कैडेट्स को अंततः उनके द्वारा चुने गए सेना के किसी एक विंग में कमीशंड ऑफिसर के रूप में नियुक्ति किया जाता है।

जॉब के प्रति लगाव जरूरी

यह सच है कि अधिकांश लोगों को अपना काम पसंद नहीं होता। कुछ उसे अधूरे मन से करते हैं, कुछ उसे बर्दाश्त करते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, जिन्हें अपनी पसंद का काम मिला हो और वह उससे अपनी जीवनशैली को भी सपोर्ट कर रहे हों। तो इसका मतलब क्या यह है कि शेष सब कुंठाग्रस्त रहें और ऐसे काम की तलाश में जुटे रहें, जो उन्हें पसंद हो। नहीं, ऐसा नहीं है।

आपको अपने कार्य का आनंद लेना चाहिए। ऐसा आपके जीवन के लिए, कई मायनों में कारगर रहेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको जॉब पसंद ही हो। जॉब और उसे अपने तरीके से अंजाम देने में फर्क होता है। यह जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते। फिर भी उन्हें हंसते हुए पूरा करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए सेल्स का काम ही लीजिए। बहुत कम लोगों में सेल्स कार्य की क्षमता होती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों को भी इससे कभी-कभार जुडना पड़ता है। कई बार तो ऐसे लोगों पर सेल्स की नीति तय करने तक की जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो चाहे आपका बॉस आपके कार्य को पसंद न करता हो, आपको कम वेतन मिलता हो, कंपनी आपकी दृष्टि में आदर्श न हो.. पर इन समस्याओं के बारे में आप केवल इतना सोचें कि आपकी क्षमताओं की असली परख आपकी अपनी श्रेष्ठतम क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए।

इसकी शुरुआत प्रत्येक दिन के अंत में अपने कार्य के प्रति खुद को शाबाशी देने से शुरू करें। इससे आपको कंपनी के अंदर या बाहर ऐसे कार्य को खोजने की भी प्रेरणा मिलेगी, जो आपको पसंद है। और आप पाएंगे कि अपनी जॉब के जो पक्ष आपको पसंद नहीं हैं, वह धीरे-धीरे लाभदायक साबित हो रहे हैं।

जीवन में आपके और क्या शौक हैं? क्या आपको पढने-लिखने का शौक है? कुकिंग, स्पोर्ट्स, कारें या कपड़े पसंद हैं। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त, प्रेमी या परिवार है, जो आपके जीवन की धुरी है? यदि ऐसा कुछ है तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको जीवन का एक मतलब मिला है। लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें लापरवाही से न लें, विशेषकर जिन लोगों का आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व है, उनके प्रति तो बिल्कुल लापरवाह न रहें। इसका मतलब यह नहीं कि जो कार्य आपको पसंद नहीं, उसके साथ ताउम्र चिपके रहें। यदि आपकी जॉब पसंद की नहीं है तो नए सोपान तलाशने शुरू कर दें। पर जरूरी है कि इसके लिए एक विधिवत योजना बनाएं। यह भी याद रखें कि एक ओर नौकरी तलाशते रहें और दूसरी ओर अपनी मौजूदा जॉब के कुछ रोचक पहलुओं को आत्मसात करते रहें। यही अनुभव आगे भी काम आएगा।

जुनून है तो बनें पायलट

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी सभी तरह के जॉब में पायलट की नौकरी युवाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहां न केवल भरपूर पैसा है, बल्कि अनोखा रोमांच भी इस जॉब में है। जहां तक सैलॅरी की बात है, तो एक कॉमर्शियल पायलट की औसत सैलॅरी एक लाख से शुरू होकर साढ़े चार लाख प्रति माह तक हो सकती है। इन दिनों एविएशन इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियों के आने से पायलट की डिमांड खूब है।

बढ़ती मांग

भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से विकास कर रहा है। दरअसल, सरकार की ओपन स्काई पॉलिसी ने इस इंडस्ट्री को अनेक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से जुडने का मौका दिया है। परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में न केवल प्राइवेट एविएशन प्लेयर्स, बल्कि एयरक्राफ्ट की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। सच तो यह है कि आगामी आठ-दस सालों में छह हजार से ज्यादा पायलट की मांग बढ़ती रहने की संभावना है।

कैसे होगा आगाज?

यदि आप पायलट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस से अवगत होना होगा, जैसे-कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए एसपीएल यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करना होता है, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपने बारहवीं में साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स) पढ़ा हो और खुद को मेडिकली फिट भी पाते हों। यदि इस फील्ड में करियर का आगाज करने के लिए उम्र-सीमा की बात करें, तो महज 16 वर्ष में ही आप फ्लाइंग के योग्य हो सकते हैं और 65 वर्ष की अवस्था तक इस करियर का आनंद ले सकते हैं।

कैसे मिलेगी एसपीएल सर्टिफिकेट

एसपीएल सर्टिफिकेट पाने के लिए यह जरूरी है कि बारहवीं में साइंस हो और आपकी न्यूनतम उम्र हो 16 वर्ष। इसके बाद डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (डीजीसीए) में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ-साथ बैंक गारंटी भी हो। डीजीसीए में पंजीकरण कराने के बाद आपको एक मौखिक परीक्षा से भी गुजरना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में पास होने के बाद ही कोई एसपीएल सर्टिफिकेट के योग्य हो सकता है।

पीपीएल प्राप्त करने के लिए ...

एसपीएल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस की जरूरत होती है। इसे प्राप्त करने के बाद ही कैंडिडेट खुद उड़ान भरने के योग्य बन सकता है। आप पीपीएल लाइसेंस के योग्य हैं या नहीं, यह एक लिखित परीक्षा के पास करने के बाद ही तय होता है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए भी बारहवीं में साइंस विषय होना चाहिए, और न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 17 वर्ष। इसके साथ-साथ आर्म्ड फोर्सेज सेंट्रल मेडिकल एस्टाविल्समेंट यानी एएफसीएमई से आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा।

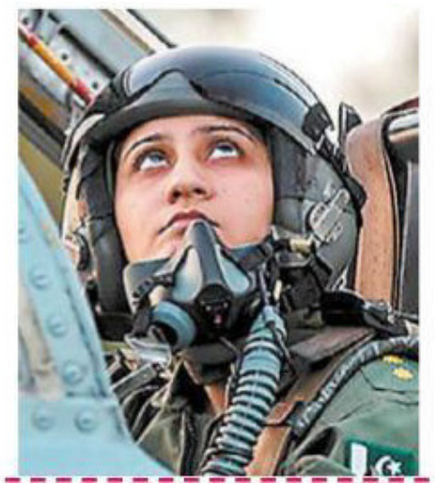

क्या पढ़ाया जाता है

कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स निम्नलिखित विषयों की बारीकियों से अवगत होते हैं..

एयर रेगुलेशंस

एविएशन मेटिओरोलॉजी, एयर नेविगेशन

एयरक्रॉफ्ट इंजिन (टेक्निकल और स्पेसिफिक दोनों)

प्लानिंग ऐंड कम्युनिकेशन (रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन के रूप में) आदि।

कौन हैं योग्य कैंडिडेट?

इस फील्ड में आने के लिए यह जरूरी है कि आई-साइट बेहतरीन हो। हाथ और पैरों का तालमेल यानी मोटर स्किल्स कॉर्डिनेशन काफी अच्छा हो।

यहां हैं संभावनाएं

शुरुआती दौर में आप किसी छोटे स्तर के एयरक्राफ्ट में ट्रेनी पायलट के रूप में जॉब कर सकते हैं। वैसे, एक कॉमर्शियल पायलट के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में करियर का आगाज कर सकते हैं..

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में

ह्वप्राइवेट एयरलाइंस में जैसे-जेट एयरवेज, सहारा, एयर डक्कन, किंगफिशर आदि।

ह्वइंटरनेशनल एयरलाइंस में, जिनका संचालन इंडिया से किया जाता है, जैसे- एयर कनाडा, कंतास, लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज आदि।

ट्रेनिंग की फीस

एडमिशन या ट्रेनिंग की फीस अलग-अलग फ्लाइंग स्कूलों पर निर्भर करती है। अमूमन भारत में सीपीएल यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (200 घंटे की फ्लाइंग) के लिए 22 से 25 लाख के बीच फीस होती है। इसमें बोर्डिंग, यूनिफॉर्म आदि की फीस भी शामिल है (हालांकि मल्टीपल इंजिन के उड़ान की फीस इसमें शामिल नहीं होती है)। वहीं अब्रॉड में ट्रेनिंग की फीस 16 से 22 लाख के बीच होती है। हालांकि यह अलग-अलग देशों पर ही निर्भर करती है कि वहां कितनी फीस की डिमांड की जा सकती है! हां, ट्रेनिंग की अवधि होती है 14-18 महीने की।

कौन हो सकते हैं सफल पायलट?

एक सफल पायलट बनने के लिए जरूरी है कि आप न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हों। याद रखें, बेस्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे, जब आपमें फ्लाइंग के प्रति जुनून होगा। साथ ही, आंख, हाथ, पैर और ब्रेन के बीच बेहतर सामंजस्य बेहद जरूरी है।

गवर्नमेंट की पहल

गवर्नमेंट ने फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि डीजीसीए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के लिए नए मापदंड तैयार करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके।

फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत

एविएशन तेजी से विकास कर रहे इंडस्ट्रीज में से एक है। आने वाले आठ से दस वर्षों में 6 हजार से अधिक पायलट की जरूरत होगी। हालांकि इसके लिए फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग की क्वालिटी ट्रेनिंग (ग्राउंड और स्काई) के पर्याप्त इक्वीपमेंट्स के साथ-साथ ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत है।

प्रशिक्षण संस्थान

- एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी, इंदौर
- ब्लू डायमंड एविएशन, पुणे
- एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग, दिल्ली
- इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन, आईएसए, नई दिल्ली
- इंडियन एविएशन एकेडमी, मुंबई

कॅरियर का चुनाव रुचि के अनुसार ही करें

आज करियर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ब्यूटी, फैशन , तकनीकी कला, हैल्थ, डिजाइनिंग इत्यादि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें यंगस्टर्स को अपनी सामर्थ्य, क्षमता एवं योग्यता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने का मौका मिलता है।

जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है अपने करियर का चुनाव करना। इसलिए करियर का चुनाव करते वक्त संबंधित क्षेत्र को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर व्यक्ति में कोई न कोई ख़ास विशेषता होती है, नहीं होती है तो उसे पहचानने की शक्ति। इस गुण को कोई यदि सकारात्मक रूप से ले तो उसके लिए करियर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि अपने स्किल्स के हिसाब से पहले ही करियर तय कर लें, जिससे आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कुछ सरल तरीक़े हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं।

सकारात्मक रुख़- विचार हमेशा आशावादी रखने चाहिए, जिससे लोगों को प्रभावित करना आसान हो जाता है। काम करके तो हर व्यक्ति थक जाता है, पर ज़िंदादिली का अहसास काम के माहौल में उब नहीं फैलने देता। आजकल हर दफ्तर में काम का दबाव बहुत होता है, ऐसे में नियोक्ता अपने कर्मचारियों से उम्मीद करता है कि वे दफ्तर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर कंपनी में सद्भावना का माहौल बनाए रखें। चाहे काम कितना भी मुश्किल हो, टारगेट पूरा करना कितना भी कठिन क्यों न हो, पॉजिटिव एटीट्यूट रखने वाले लोग अपना और अपने टीम मेंबर का उत्साह बनाए रखते हैं और काम को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्किल की ज़रूरत डेस्क-जॉब, जैसे अकाउंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रांसलेटर, एडिटिंग, सब एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग इत्यादि में ख़ास कर होती है। इसलिए माहौल को हल्का बनाने की क्षमता रखने वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले औसत व्यक्ति भी इन क्षेत्रों को चुन सकते हैं।

संवाद- बेहतरीन भाषा और बोल-चाल आपके करियर को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, यह शायद आप सोच भी नहीं सकते। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, जो वाकपटुता से अपने आस-पास के माहौल को अनुकूल बना लेते हैं। दरअसल किसी भी काम को करते या बोलते समय अपना पूरा ध्यान काम पर लगा पाने के साथ ही यह आंक लेना कि सामने वाला किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है और किस प्रकार सामने वाले को आकर्षित किया जा सकता है, ऐसी ही योग्यता को बेहतरीन कम्यूनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ऐसे स्किल की ज़रूरत आज कई क्षेत्रों में है, जैसे-मार्केटिंग, एंकरिंग, जॉकिइंग, टेलीकॉम, टूरिज़्म, लैंग्वेज़ , पीआर इत्यादि।

रॉबिन्सन पर कार्रवाई के बाद एंडरसन सहित कई अन्य खिलाड़ी भी ईसीबी के निशाने पर आये

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) विवादित ट्वीट के मामले में तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के निलंबन के बाद अब ऐसे सभी खिलाड़ियों पर कार्रवाई के मूड में है जिन्होंने पूर्व में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणियां की हैं। रॉबिन्सन पर आठ साल पुराने मामले में ईसीबी के इस कदम के बाद अब अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एंडरसन ने भी 11 साल पहले अपने एक ट्वीट में स्टुअर्ट ब्रॉड को लेस्बियन कहा था। एंडरसन ने ये ट्वीट फरवरी 2010 में किया था। तब उन्होंने ब्रॉड के लिए लिखा था कि मैंने आज पहली बार ब्रॉडी का नया हेयरकट देखा। इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। सोचा था कि वह 15 साल के लेस्बियन की तरह लग रहा था। वहीं अपने इस ट्वीट को लेकर एंडरसन ने सफाई दी है कि मेरे लिए ये 10-11 साल पहले की घटना है। वहीं अब मैं एक व्यक्ति के रूप में काफी बदल गया हूं और मुझे लगता है कि यही मुश्किल है, चीजें बदलती रहती हैं और आप गलतियां करते हैं।

रॉबिन्सन मामले के बाद एंडरसन ही नहीं बल्कि पूर्व कप्तान ऑयन मोर्गन, जोस बटलर, कप्तान जो रूट और डॉम बेस समेत इंग्लैंड के कई क्रिकेटरों के विवादित ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रॉबिन्सन के विवाद के बाद इन खिलाड़ियों के भी 10 साल पुराने पोस्ट सामने आए हैं, जो कथित तौर पर इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुए हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों की भी परेशानी बढ़ सकती है। इसका कारण है कि ईसीबी ने अब हर मामले में जांच की बात कही है। रॉबिन्सन के ट्वीट विवाद के बाद बाकी खिलाड़ियों की भी चिंता बढ़ गई है। एंडरसन ने कहा कि भविष्य को लेकर हम आशंकित हैं। अगर सालों पहले का कोई ट्वीट है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा और भविष्य में सतर्क रहना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है और इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा।

एक दिन पहले ही ईसीबी ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा था कि हम रॉबिन्सन के मामले के बाद सतर्क हो गए हैं। इसलिए अतीत में कई और खिलाड़ियों द्वारा किए गए विवादित पोस्ट जिस पर सार्वनजिक रूप से सवाल खड़े किए गए हैं, उस पर भी हमारी नजर है। हमारे खेल में भेदभाव की कोई जगह नहीं है। हम जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ये सिर्फ एक मामला नहीं है। हर मामले को अलग तरीके से देखा जाएगा। सभी तथ्यों के आंकलन के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

अश्विन के ट्वीट पर बोले जाफर, अच्छा हुआ मैं संन्यास के बाद ट्विटर से जुड़ा

मुम्बई, (एजेंसी)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के विवादास्पद ट्वीट मामले में निलंबन पर भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने कहा था कि भविष्य में सोशल मीडिया जनरेशन के साथ क्या कुछ हो सकता है यह उन्हें जान लेना चाहिये। वहीं इसपर इस पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने मजे लेते कहा कि, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं संन्यास लेने के बाद ही ट्विटर से जुड़ा हूं। निलंबन के बाद रोबिन्सन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 जून से शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। रोबिन्सन के बाद कई अन्य क्रिकेटरों के ट्वीट भी जारी हुए हैं जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसपर कार्रवाई होगी। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज अभी बराबरी पर है, ऐसे में जो भी दूसरे मैच में जीत दर्ज करेगा, वह मैच के साथ टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। बता दें कि यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का हिस्सा नहीं है।

पेरिस में फ्रैंच ओपन टेनिस में यूनान के स्टीफिनोस टेसिसपास रुस के डेनिल मेदवदेव को हराने के बाद उत्साहित नजर आये।

रमीज ने मेसी से विराट को जोड़ा, कहा उन्हें भी अपनी कप्तानी में बड़े खिताब का है इंतजार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की स्थिति को बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी से जोड़ते हुए कहते हैं कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल जैसे टूनार्मेंटों में इतने आगे तक जाना टेंपरामेंट (जूनून) की बात होती है। कोहली महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईसीसी विश्व कप 2011 विजेता टीम में शामिल थे पर अभी तक वह अपनी कप्तानी में भारतीय टीम के लिए कोई बड़ा खिताब नहीं जीत पाये हैं। इसलिए उनका लक्ष्य किसी भी प्रकार से डब्ल्यूटीसी खिताब जीतना रहेगा।

रमीज ने कहा कि अब विराट के पास विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में एक अच्छा अवसर है, जिसे वह अपनी उपलब्धि में जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसी साल टी20 विश्व कप भी है हालांकि, बहुत से लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को बड़ा अवसर मानते हैं।

रमीज ने कहा, सर विवियन रिचर्ड्स को देखिए। वह हमेशा बड़े मौकों पर प्रदर्शन करते थे। इसी प्रकार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विराट के लिए बड़ा मौका है कि वह शतक बनाए और भारत को ट्रॉफी दिलाएं। वह पहले ही लीजेंड्स में शामिल हैं, लेकिन भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी दिलाना उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ देगा। इस तरह का मंच कोहली के लिए ऑल टाइम ग्रेट्स के क्लब में प्रवेश करने का एक शानदार मौका है। उनमें ऐसा करने की क्षमताएं भी है। बस उन्हें अपनी प्रतिभा को परिस्थिति के अनुसार मैनेज करने की जरूरत है। रमीज ने विराज के साथ मेसी का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि स्टार फुटबॉलर होने के बाद भी मैसी अपनी टीम अर्जेंटीना के लिए अब तक एक भी बड़ा खिताब नहीं जीत पाये हैं।

उन्होंने कहा, कुछ बड़े नाम जैसे मेसी को अभी अर्जेंटीना के लिए बड़ा खिताब जीतना है। यह सब टेंपरामेंट की बात है। विश्व कप फाइनल जैसे बड़े खेलों में प्रदर्शन करना खिलाड़ी की योग्यता साबित करता है।

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे में वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम देगा सीए

मेलबर्न, (एजेंसी)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे के लिए अपने शीर्ष खिलाड़ियों को आराम दे सकता है। सीए के अनुसार लंबे समय तक जैव सुरक्षित माहौल में रहने के कारण इन खिलाड़ियों को आराम की जरुरत है। माना जा रहा है कि इसी कारण सीए ने 10 जुलाई से शुरू होने वाले सीमित ओवरों के इन मैचों के लिये अपनी संभावित टीम में छह नए खिलाड़ी भी शामिल किए हैं। सीए की चयन समिति ने बेन मैकडरमॉट, डैन क्रिश्चियन, कैमरन ग्रीन, एश्टन टर्नर, वेस एगर और नाथन एलिस जैसे युवाओं को टीम में अवसर दिया है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलियाई दल की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी और उसके अगस्त के शुरू में पांच टी20 मैचों के लिए बांग्लादेश का दौरा करने की संभावना है। टीम 28 जून को चार्टर्ड विमान से वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी। उससे पहले टीम में बदलावों के तहत ही अनुभवी खिलाड़ियों को ब्रेक दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष ट्रेवर हॉन्स ने कहा है कि वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे के लिए संभावित टीम में शुरू में चुने गए खिलाड़ियों के साथ चर्चा के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम में छह नए खिलाड़ी शामिल किये गए हैं। तेज गेंदबाजी आलराउंडर डेनियल सैम्स पहले ही मानसिक स्वास्थ्य कारणों से बाहर हो गए हैं जबकि स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर और पैट कमिन्स भी इन दौरों से बाहर रह सकते हैं। हॉन्स ने कहा कि जैव सुरक्षित वातावरण में रहना और कड़े पृथकवास सहित विदेशों के हाल के अनुभव का खिलाड़ियों और उनके परिवार पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सीए की पहली प्राथमिकता अपने खिलाड़ियों स्टाफ और अधिकारियों की सेहत का ध्यान रखना है।

30 जुलाई से शुरू होगी श्रीलंकाई प्रीमियर लीग

कोलंबो, (एजेंसी)। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के अनुसार श्रीलंकाई प्रीमियर लीग (एलपीएल) टी-20 टूनार्मेंट का दूसरा सत्र अगले माह 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच जैव-सुरक्षित वातावरण (बायो-बबल) में खेला जाएगा। एसएलसी यह बताना चाहता है कि पहले की घोषणा के अनुसार लंका प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

दूसरे टेस्ट में उतरते ही इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक टेस्ट खेलने का कुक का रिकार्ड तोड़ेंगे एंडरसन

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन गुरुवार को मेहमान टीम न्यूजीलैंड के खिताफ मैदान पर उतरते ही एक अहम रिकार्ड अपने नाम करेंगे। यह मैच खेलने के बाद वह इंग्लैंड की ओर से पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक के सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने के रिकार्ड को तोड़ देंगे। यह उनका 162वां टेस्ट मैच होगा जो इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक है। कुक ने 161 टेस्ट मैच खेले थे।

एंडरसन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के यह 15 साल सच अविश्वसनीय रहे हैं। यह जानकर कि कुक ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं सच में इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इसमें कुछ साल लग गए। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी दुनिया की बेहतर टीमों के खिलाफ खेलना थोड़ा मुश्किल है। एक बार जब आप दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तब आप महसूस कर सकते हैं कि आप सच में उस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए मुझे यह सोचने पर मजबूर करने में कुछ साल और दुनिया भर के कुछ दौरे लगे कि मैं सच में ऐसा कर सकता हूं। गौरतलब है कि एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया था। इस मेज गेंदबाज ने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। एंडरसन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह काऊंटी क्रिकेट से बहुत बड़ा कदम है। मुझे याद है कि मेरे पहले मैच में तब के कप्तान नासिर हुसैन ने फाइन लेग पर फील्ड नहीं लगाई थी और मैं काफी रन दे चुका था। मेरी पहली गेंद भी नो बॉल थी, इसलिए उस समय मैं काफी नर्वस था और उस समय मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं यहां तक पहुंचुंगा।

पेरिस में स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक महिला एकल टेनिस मुकाबले में रिटर्न शॉट लगाती हुई।

टोक्यो ओलंपिक में पहली बार दो ध्वजवाहकों के साथ उतरेगा भारत : बत्रा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत आगामी टोक्यो ओलंपिक में पहली बार दो ध्वजवाहकों के साथ उतर सकता है इसमें एक पुरुष जबकि एक महिला होगी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा कि लैंगिक समानता का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। बत्रा ने साथ ही यह भी कहा कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह मामला अब भी सलाह मशविरे के चरण पर है लेकिन संभावना है कि इस साल लैंगिक समानता के लिए दो ध्वजवाहक- एक पुरुष और एक महिला शामिल होंगे।

गौरतलब है कि पिछले रियो ओलंपिक खेलों में ध्वजवाहक देश के एकमात्र ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने पिछले साल अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में उद्घाटन समारोह के दौरान दोनों लिंग के ध्वजवाहकों को शामिल करने का प्रावधान किया था।

तब आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने कहा था कि आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने फैसला किया है कि पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही सभी 206 टीमों और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम में कम से कम एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अपने नियमों में बदलाव किया है जिससे कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एक पुरुष और महिला खिलाड़ी को नामित कर सकें जो उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त रूप से उनके ध्वजवाहक बनें। हम सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को प्रेरित करेंगे कि वे इस विकल्प का इस्तेमाल करें। टोक्यो खेलों का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। इन खेलों में भारत के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।

क्रोएशिया दौरे से अभ्यास का अच्छा अवसर मिला : मनु भाकर

जागरेब, (एजेंसी)। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर के अनुसार आगामी टोक्यो ओलंपिक से पहले क्रोएशिया दौरे से सभी निशानेबाजों को बेहद लाभ हुआ है। मनु ने कहा कि इस दौरे से जिस प्रकार के अभ्यास का अवसर मिला ओलंपिक के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था।

भारतीय निशानेबाज ओसियेक में आमंत्रित टीम के रूप में यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद अब जागरेब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये निशानेबाज आसियेक में 22 जून से तीन जुलाई तक होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप में भी चुनौती पेश करेंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में शिविर का आयोजन संभव नहीं था और ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने क्रोएशिया दौरे का आयोजन किया था। मनु ने कहा कि इस दौरे से काफी मदद मिली।

साथ ही कहा कि इस दौरे में हमारा, हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस जरूरतों का अच्छी तरह ध्यान रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण हमें बेहद अच्छी निशानेबाजी रेंज में ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है और साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि ओलंपिक खेलों से पहले इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। इस पदक दावेदार निशानेबाज ने कहा कि वह अपेक्षाओं के बोझ तले दबने से बचना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूं। मैं इसके अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही, बस खेलों में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान है।

रैना ने अपनी किताब में लिखा, धोनी से दोस्ती नहीं अपने क्षमताओं के कारण टीम इंडिया में मिली थी जगह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा है कि वह अपनी काबिलियत के कारण टीम इंडिया में शामिल थे। इसलिए ये कहा जाना कि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी से दोस्ती के कारण उन्हें टीम में जगह मिली थी गलत है। रैना ने यह बात अपनी किताब बिलीव में कही है। रैना ने इस किताब में लिखा है कि उन्हें कई बार यह बात सुनने को मिली कि धोनी से दोस्ती की वजह से वो टीम इंडिया में हैं जोकि पूरी तरह आधारहीनी बात थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी अपनी क्षमताओं के बल पर ही खेल सकता है। रैना ने हालांकि अपनी किताब में धोनी की तारीफ करते हुए लिखा, धोनी जानते थे कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे हासिल किया जा सकता है और मैंने भी उनपर भरोसा किया पर उस समय बहुत दुख होता है जब लोग हमारी दोस्ती को मेरी टीम इंडिया में जगह पाने से जोड़ दिते हैं। मैंने हमेशा टीम इंडिया में अपनी जगह वैसे ही हासिल की जैसे मैंने धोनी का भरोसा और सम्मान हासिल किया है। गौरतलब है कि धोनी और रैना की दोस्ती काफी पुरानी है। धोनी और रैना लगभग साथ ही टीम इंडिया में आए थे। धोनी ने 2004 और रैना ने 2005 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कई मैच जिताए। इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद ही रैना ने भी खेल को अलविदा कह दिया। धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा और उन्हीं के संन्यास के कुछ देर बाद ही रैना ने भी संन्यास ले लिया।

कार्तिक ने टीम इंडिया को इतिहास की बेस्ट टीम बताया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि भारत की वर्तमान टीम टेस्ट इतिहास की सबसे बेहतर टीम है। कार्तिक ने कहा, मौजूदा टीम की तुलना 1971 की अजीत वाडेकर की टीम से की जा सकती है लेकिन मेरे हिसाब अभी की हमारी टीम टेस्ट इतिहास की बेस्ट टीम है।

डब्ल्यूटीसी फाइनल में अंतर पैदा करेंगे अश्विन : पनेसर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल रोमांचक रहेगा क्योंकि दोनो ही टीमें काफी अच्छी हैं। न्यूजीलैंड की ओर से जहां तेज गेंदबाज टिम साउदी अच्छी फार्म में हैं, वहीं भारत की ओर से अनुभवी स्पिनर आर अश्विन मैच विजेता साबित हो सकते हैं। पनेसर के अनुसार अश्विन का प्रदर्शन एशियाई पिचों के बाहर भी शानदार रहा है। टेस्ट इतिहास में अश्विन अकेले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने 200 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है।

पनेसर ने कहा कि न्यूजीलैंड टेस्ट टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऐसे में अश्विन का सामना करना उन बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। पनेसर ने कहा, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम है और युवा बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी। उनकी टीम में काफी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो मुझे भरोसा है कि स्पिनर के तौर पर अश्विन ही टीम इंडिया की पहली पसंद होंगे। इंग्लैंड में जो लोग सोचते हैं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड उससे बहुत बेहतर टीम है। वह नंबर-1 टीम जैसी है।

उन्होंने साथ ही कहा, मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच काफी रोमांचक होगा। यह भारत के लिए आसान नहीं होगा पर मौसम को देखते हुए और साथ ही न्यूजीलैंड में कई बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए अश्विन इस फाइनल मैच में मैच विजेता साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अश्विन अंतर पैदा करेंगे, कीव टीम की ओर से साउदी अच्छी फॉर्म में हैं और वह न्यूजीलैंड के लिए अंतर पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत की संभावनाएं इस गेंदबाज के प्रदर्शन से बढ़ जाएंगी।

ब्रिगगिव्यू में कनाडा के एलिस्टर जॉनस्टन विश्व कप फुटबॉल क्वालीफायर में हैडर करते हुए।